वर्ष- चार अंक- 05 अगस्त - 2024 मूल्यः 20

राष्ट्रीय मासिक पत्रिका

नवजीवन संदेश

11वीं बार लालकिले से ध्वजारोहण

RNI No : JHAHIN/2021/83133

कोल इण्डिया
Coal India

पर्यावरण की
सुरक्षा का संकल्प

इस संकल्प ने हमारे मन मानस में गहरी जड़ पकड़ ली है

नरेंद्र मोदी का राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन, ... पेज-09

मोरहाबादी मैदान में मुख्यमंत्री हेमंत ने किया .. 09

Yuvraj की जिंदगी पर बायोपिक का..... 33

index

RNI No: JHAHIN/2021/83133

नवजीवन संदेश

राष्ट्रीय मासिक पत्रिका

Web : navjeewansandesh.com

संबद्धता : प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (भाषा)

▪ वर्ष -3, ▪ अंक -04, ▪ कुल पृष्ठ -36

प्रधान संपादक

पंकज कुमार सिंह

संपादक

प्रभात मजुमदार

संपादकमंडल

जगन्नाथ मुंडा

सुनीता सिन्हा

श्रीमती छाया

रविप्रकाश

खेल डेस्क प्रभारी

चंचल भट्टाचार्य

छायाकार

नसीम अख्तर

संपर्क : 9431708799

9835437102

ईमेलः navjeewansandesh@gmail.com

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक और प्रकाशक पंकज कुमार सिंह द्वारा प्रथम तल, होटल आलोका कॉम्प्लेक्स रेडियम रोड, समीप कचहरी चौक, रांची-834001 (झारखंड) से प्रकाशित तथा मैसर्स डी।,बी। कॉर्प लि। प्लॉट नंबर 535 व 1272, लालगुटवा, पुलिस स्टेशन रातू रांची से मुद्रित।

संपादक : प्रभात मजुमदार* (*संपादक इस अंक में प्रकाशित समाचार के चयन एवं संपादन हेतु पीआरबी एक्ट की धारा 7 के अंतर्गत उत्तरदायी)

आरएनआई नं.: JHAHIN/2021/83133

संपादकीय

अभिव्यक्ति की आजादी

अभिव्यक्ति की आजादी पर हमले के आरोपों के बाद सरकार द्वारा एक विवादास्पद प्रसारण विधेयक को फिर से लिखने के फैसले का डिजिटल अधिकार कार्यकर्ताओं और ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर्स ने स्वागत किया है. उन्हें डर था कि इससे इंटरनेट पर बोलने की स्वतंत्रता पर लगाम लग सकती है. लेकिन उन्होंने चेतावनी दी है कि सरकार नए विधेयक में भी कुछ कठोर प्रावधान रख सकती है जो भारत की तेजी से विकसित होती डिजिटल दुनिया को प्रभावित कर सकते हैं.

डॉ. मेडुसा एक राजनीतिक व्यंग्यकार हैं, जिनके यूट्यूब, इंस्टाग्राम और एक्स पर 265,000 से अधिक फॉलोअर्स हैं. उन्होंने कहा, "यह (नए विधेयक का फैसला) एक बहुत ही खुशी की बात है. लेकिन हमें अभी भी बहुत सतर्क रहना होगा. हमें हमेशा तैयार रहना होगा और देखना होगा कि आगे क्या होता है." डॉ. मेडुसा ने सुरक्षा कारणों से सोशल मीडिया नाम से पहचान बताने का अनुरोध किया था. सरकार ने कहा है कि नया प्रसारण कानून अधिक पारदर्शिता लाएगा. हालांकि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टिप्पणी के लिए भेजे गए अनुरोधों का जवाब नहीं दिया.

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की निगरानी करने वाली संस्था फ्रीडम हाउस के अनुसार, इंटरनेट बंद करने, सोशल मीडिया से सामग्री हटाने और पत्रकारों, कार्यकर्ताओं और सोशल मीडिया पर अपनी बात कहने वाले लोगों की गिरफ्तारियां इंटरनेट स्वतंत्रता को सीमित करती हैं. इस मामले में भारत को "आंशिक रूप से स्वतंत्र" देश के रूप में रैंक किया गया है.

नए विधेयक का प्रस्ताव ऐसे समय पर आया है जब भारत में स्ट्रीमिंग कंपनियों और डिजिटल निर्माताओं पर निगरानी बहुत बढ़ गई है. सिनेमा में सभी फिल्मों की समीक्षा और सर्टिफिकेशन सेंसर बोर्ड द्वारा किया जाता है लेकिन स्ट्रीम की गई और डिजिटल सामग्री की समीक्षा की फिलहाल कोई व्यवस्था नहीं है.

पिछले नवंबर में प्रसारण क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए एक ड्राफ्ट विधेयक पेश किया था, जिसमें नेटफ्लिक्स और अमेजन जैसी स्ट्रीमिंग वेबसाइटों को शामिल किया गया था. बाद में, विधेयक के एक संशोधित मसौदे में सभी डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स को शामिल कर लिया गया. इनमें सोशल मीडिया अकाउंट्स, ऑनलाइन वीडियो निर्माता और पॉडकास्टर्स तक हर तरह के कंटेंट क्रिएटर्स शामिल हैं. तकनीकी नीति विश्लेषकों के अनुसार इस मसौदे को सार्वजनिक

नहीं किया गया था.

इन सभी "प्रसारकों" को सरकार के साथ पंजीकरण कराने, सामग्री के मूल्यांकन के लिए एक समिति स्थापित करने और शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त करने की आवश्यकता होती, जो उनके द्वारा तैयार सामग्री से संबंधित शिकायतें सुनता. नियमों का उल्लंघन करने पर आपराधिक मुकदमे, जेल की सजा, उपकरणों की जब्ती व बिना वारंट के छापे जैसी कार्रवाइयों का सामना करना पड़ सकता था. थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन इस ड्राफ्ट के विवरण की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं कर सका. सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने ड्राफ्ट विधेयक के विवरण या आगामी योजना पर कोई जानकारी नहीं दी.

इन नियमों की लंबी सूची ने डिजिटल सामग्री निर्माताओं को चिंतित कर दिया है. वे इन्हें जटिल, महंगा और समय लेने वाला मानते हैं. स्वतंत्र पत्रकार और यूट्यूबर मेघनाद एस. के लगभग 66 हजार सब्सक्राइबर हैं. वह कहते हैं कि इससे छोटे निर्माताओं को "अस्तित्व के संकट" का सामना करना पड़ सकता है.

मेघनाद कहते हैं, "मुझे सबसे ज्यादा डर इस बात से है कि वे मेरे सभी उपकरण ले सकते हैं. मेरे पास नए उपकरण खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं. इस समय मेरे यूट्यूब चैनल से किराया देना एक बड़ी बात है."

प्रसारण मंत्रालय ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया कि "एक नया ड्राफ्ट विस्तृत परामर्श के बाद प्रकाशित किया जाएगा," और सुझाव और फीडबैक प्राप्त करने की अवधि 15 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है. पिछले ड्राफ्ट को वापस लिया जाना डिजिटल अधिकार कार्यकर्ताओं और ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक छोटी जीत थी, लेकिन उन्होंने कहा कि जश्न मनाने का समय अभी नहीं आया है.

डिजिटल अधिकार कार्यकर्ता और मीडिया नामा के संपादक निखिल पाहवा ने कहा, "हमें मंत्रालय से अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता है. मंत्रालय ने पिछले कुछ महीनों में उद्योग के साथ निजी बैठकें की हैं, और ऑनलाइन क्रिएटर, डिजिटल अधिकार समूहों और डिजिटल समाचार प्रकाशकों को बाहर रखा है."

अधिकार समूहों ने कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि सरकार हालिया ड्राफ्ट विधेयक को पूरी तरह से हटा रही है और क्या नए संस्करण के लिए सभी पक्षों के साथ बातचीत करेगी. ज्यादातर तकनीकी विशेषज्ञों और सामग्री निर्माताओं ने उम्मीद जताई कि सरकार अगले संसद सत्र में विधेयक पेश करेगी, जो शायद नवंबर के मध्य में शुरू होगा.

मेघनाद कहते हैं, "अब हमें शीतकालीन सत्र का इंतजार है. देखना है कि वे क्या नया संस्करण लाते हैं और उसे जल्दी से पारित करने की कोशिश करते हैं. अभी वे पीछे हट रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या यह (पिछला ड्राफ्ट) हमेशा के लिए रद्द हो गया है."

प्रधानमंत्री मोदी ने 11वीं बार स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर तिरंगा फहराया

ऐसा करने वाले वह तीसरे पीएम, उनके पहले पंडित नेहरू ने 17 बार, इंदिरा गांधी ने 16 बार लाल किले से झंडा फहराया

78वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर तिरंगा फहराया। अपने 103 मिनट के भाषण में पीएम ने कहा कि देश में अगले 5 साल में 75 हजार मेडिकल सीटें बढ़ाई जाएंगी। वहीं कोलकाता रेप-मर्डर पर उन्होंने कहा- ऐसे राक्षसों को फांसी पर लटका दिया जाए।

बतौर प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार 11वीं बार लाल किले पर झंडा फहराया। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद देशवासियों को माई-बाप कल्चर से गुजरना पड़ा था। हमने गर्वनेंस के इस मॉडल को बदला है। देश में 75 सालों से कम्युनल सिविल कोड है। अब देश को सेक्युलर सिविल कोड की जरूरत है।

लाल किले पर मुख्य समारोह में शामिल होने से पहले प्रधानमंत्री ने सुबह राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। 78 वें स्वतंत्रता दिवस की थीम विकसित भारत रखी गई है। इसके तहत स्वतंत्रता के 100वें साल यानी 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है।

2047 तक विकसित भारत का संकल्प पूरा करेंगे : प्रधानमंत्री ने कहा- हमारे पूर्वज सिर्फ 40 करोड़ थे, उन्होंने गुलामी जंजीरों को तोड़ दिया था। हमारे पूर्वजों का खून हमारी रगों में है। अगर 40 करोड़ गुलामी की बेड़ियों को तोड़ सकते हैं, तो 140 करोड़ नागरिक अगर संकल्प लेकर चल पड़ें, तो चुनौतियां कितनी बड़ी क्यों न हो, हर चुनौती को पार करते हुए हम समृद्ध भारत बना सकते हैं। हम 2047 विकसित भारत का संकल्प प्राप्त कर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि देशवासियों ने अपने अनुभव से हमें विकसित भारत बनाने के सुझाव दिए हैं।

इस साल और पिछले कुछ सालों से प्राकृतिक आपदा के कारण हमारी चिंता बढ़ती जा रही है। इसमें अनेक लोगों ने अपने परिवारजन खोए हैं, अपनी संपत्ति खोई है। राष्ट्र को भी नुकसान हुआ है मैं आज उन सब के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं, उन्हें विश्वास दिलाता हूं ये देश संकट की घड़ी में उनके साथ खड़ा है।

पीएम मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री 11वें स्वतंत्रता दिवस पर 103 मिनट का सबसे लंबा भाषण दिया। पहली बार उन्होंने लालकिले से 100 मिनट से ज्यादा की स्पीच दी है। चार बार (2016, 2019, 2022, 2023) 90 मिनट से ज्यादा का भाषण दिया है। सबसे छोटा भाषण साल 2014 का है, जब मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे। तब उन्होंने 65 मिनट की स्पीच दी थी।

विकसित भारतः पीएम ने कहा- 2047 विकसित भारत हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। ये देश चलने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं तीसरे टर्म में तीन गुना काम करूंगा। ताकि देश के सपनों को पूरा कर सकूं। अब दुनिया के लिए डिजाइनिंग इंडिया पर बल देना है, अब इंडियन स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनने चाहिए। डिजाइन के क्षेत्र में हम दुनिया को बहुत कुछ दे सकते हैं।

नई शिक्षा नीतिः एजुकेशन सिस्टम में नई शिक्षा नीति आने से मातृभाषा को बल मिला। भाषा टैलेंट के रास्ते नहीं आनी चाहिए। जीवन में मातृ भाषा को बल देना होगा। आज दुनिया में जैसा बदलाव हो रहा है, अब जाकर स्किल का महत्व बढ़ गया है।

न्याय संहिताः हमने 1500 से ज्यादा कानूनों को खत्म कर दिया। छोटी गलती के चलते जेल जाने वाले कानूनों को खत्म कर दिया। आज हमने जो आजादी की विरासत की गर्व की बात करते हैं। सदियों से जो पुराने क्रिमिनल लॉ थे, उन्हें खत्म किया है। हमने दंड नहीं न्याय पर फोकस रखा।

आत्मनिर्भर भारतः डिफेंस सेक्टर में हमारी आदत हो गई थी कि बजट का पैसा कहां जाता है, विदेश से इंपोर्ट करते थे। आज इसमें आत्मनिर्भर बने हैं। आज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का हब बने हैं। दुनिया में हथियार एक्सपोर्ट कर रहे हैं।

बैंकिंग सेक्टरः बैंकिग क्षेत्र में हमने रिफॉर्म किया तो दुनिया की मजबूत बैंकों में हमारी बैंकों ने स्थान बनाया। बैंकिंग सेक्टर मजबूत हो तो विकास भी होता है, हमारे नौजवानों को पढ़ाई, विदेश जाने के लिए लोन चाहिए। किसानों को लोन चाहिए, रेहड़ी पटरी वाले भी लोन ले रहे और विकास में भागीदार बन रहे हैं।

कृषि रिफॉर्मिंगः हम किसानों की मदद कर रहे हैं, आसान लोन दे रहे हैं, उसे टेक्नोलॉजी दे रहे हैं। उसे एंड टु एंड होल्डिंग मिले उस दिशा में काम रहे हैं। आज दुनिया के लिए ऑर्गेनिक फूड बनाने वाला फूड बास्केट हमारे देश का किसान बना सकता है।

नालको NALCO

A Navratna CPSE

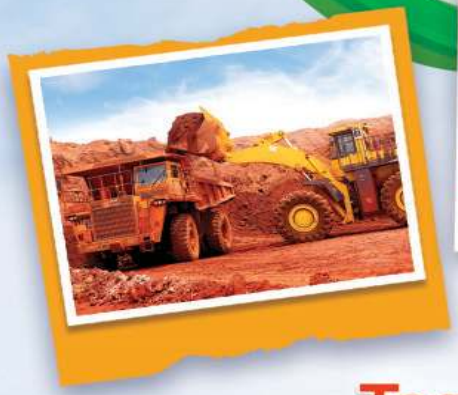

Together We Build : Strengthening Our Nation for Tomorrow

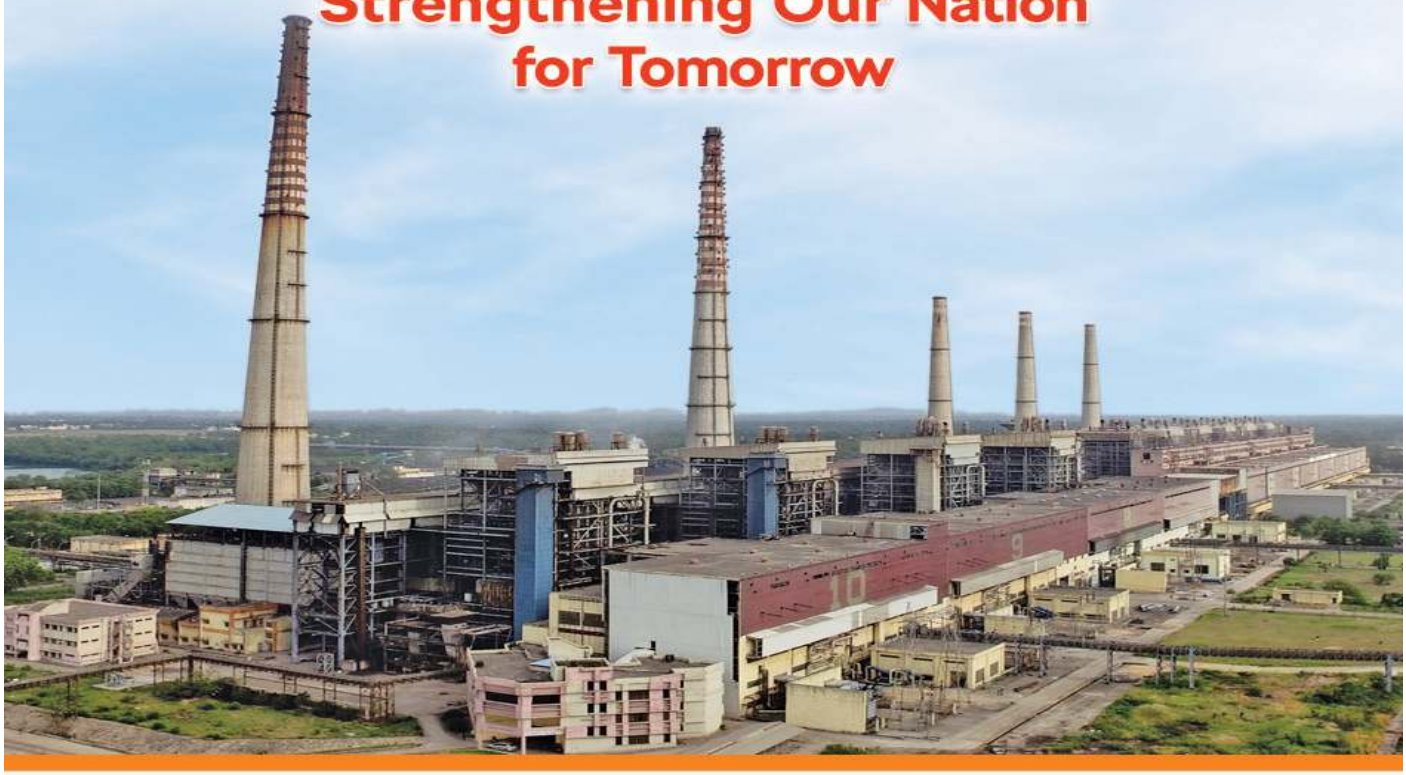

NATIONAL ALUMINIUM COMPANY LIMITED

(A Govt. of India Enterprise)

Nalco Bhavan, P/1, Nayapalli, Bhubaneswar - 751 013, Odisha

बांग्लादेश के बदलते हालात में भारत के लिए क्या विकल्प हैं

▪ चारु कार्तिकेय

बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिर जाएगी इसकी उम्मीद ना हसीना को थी ना भारत को. भारत इस अप्रत्याशित घटनाक्रम के आगे मजबूर है, लेकिन उसे एक नई रणनीति पर काम करना होगा. ऐसे में आखिर क्या विकल्प हैं भारत के सामने?

बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के गठन की प्रक्रिया पूरी हो गई है. राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने मोहम्मद यूनुस को इस सरकार का नेता नियुक्त कर दिया है. राष्ट्रपति संसद भंग कर चुके हैं और देश के संविधान के मुताबिक तीन महीनों के अंदर चुनाव हो जाने चाहिए. यानी अगले तीन महीने भारत को अंतरिम सरकार के साथ ही अपने संबंध बनाने होंगे. क्या यह भारत के लिए आसान होगा? कई जानकारों का मानना है कि भारत के लिए यह एक बड़ी चुनौती है. बांग्लादेश में भारत की पूर्व उच्चायुक्त रीवा गांगुली दास का मानना है कि बांग्लादेश में जो हुआ वो अप्रत्याशित था. उन्होंने बताया, "बांग्लादेश में सरकार के गठन के बाद से ही अशांति थी, छात्र खुश नहीं थे, प्रदर्शन हो रहे थे. लेकिन किसी ने यह कल्पना नहीं की थी कि आंदोलन इतनी जल्दी यह रूप ले लेगा." लेकिन अब भारत के सामने कैसी चुनौती है? वरिष्ठ पत्रकार नीलोवा रॉय चौधरी का मानना है कि भारत के सामने ज्यादा विकल्प नहीं हैं, क्योंकि बीते सालों में भारत सरकार ने शेख हसीना का कुछ ज्यादा ही साथ दिया.

नीलोवा ने बातचीत में कहा, "भारत ने अपने सारे अंडे शेख हसीना की टोकरी में रख दिए थे. अब उसे अपने आप को उस स्थिति से बाहर निकालना होगा, सभी मोर्चों पर अपने संबंधों को बढ़ाना होगा लेकिन शांत रह कर स्थिति पर नजर भी बनाए रखनी होगी." नीलोवा ने आगे कहा, "भारत के सामने फिलहाल तो यही विकल्प होगा कि अभी जो भी सरकार बांग्लादेश में बन रही है उसके साथ संबंध स्थापित करे. भारत को अपने पत्ते इस तरह से खेलने होंगे कि उसे बांग्लादेश के लोगों के दोस्त के रूप में देखा जाए." लेकिन कुछ जानकारों की राय इससे अलग है. भारत के रक्षा मंत्रालय के संस्थान मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस की रिसर्च फेलो स्मृति पटनायक का मानना है कि भारत के पास विकल्प मौजूद हैं.

उन्होंने बताया, "कुछ लोग कह रहे हैं कि अवामी लीग के चले जाने के बाद भारत के पास अब कोई विकल्प नहीं हैं, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूं.... ऐसा तो नहीं है कि भारत के बांग्लादेश में

किसी दूसरी सरकार से या किसी दूसरी पार्टी से कोई संबंध नहीं रहे हैं. दोनों देशों के अपने अपने राष्ट्रहित हैं और सिर्फ प्रशासन बदल जाने से राष्ट्रहित नहीं बदलता है." लेकिन नीलोवा इस बात से सहमत नहीं हैं. उनका कहना है कि भारत ने धीरे धीरे बीएनपी से अपने संबंध खत्म कर लिए थे. उन्होंने यह भी बताया कि यूनुस के मनमोहन सिंह के साथ अच्छे संबंध थे, लेकिन हसीना के कार्यकाल में जब यूनुस के खिलाफ जांच शुरू की गई और उन्हें जेल में बंद करने की कोशिश की गई तो भारत ने इसके खिलाफ कभी कुछ नहीं कहा

2011 में शेख हसीना की सरकार ने यूनुस द्वारा शुरू किए गए ग्रामीण बैंक की गतिविधियों की जांच शुरू की. जांच शुरू होने के कुछ ही दिनों में सरकार ने यूनुस को बैंक से निकाल दिया. उसके बाद एक एक कर उनके खिलाफ कई तरह के मुकदमे दायर किए गए. जनवरी, 2024 में बांग्लादेश की एक अदालत ने इन्हीं में से एक मामले में यूनुस को छह महीने जेल की सजा भी सुनाई, लेकिन बाद में उन्हें जमानत मिल गई. यूनुस को दोषी ठहराए जाने के फैसले को कई लोगों ने विवादास्पद कहा था, लेकिन भारत उनमें शामिल नहीं था.

यूनुस ने कुछ ही दिनों पहले इंडियन एक्सप्रेस अखबार को दिए एक साक्षात्कार में कहा था कि बांग्लादेश में बीते दिनों जो कुछ हुआ उस पर जब भारत ने यह कहा कि यह "बांग्लादेश का आंतरिक मामला है" तो उन्हें दुख हुआ. उनका कहना था कि कूटनीति में इस तरह के मामलों पर सिर्फ "आंतरिक मामला" से ज्यादा कहने के लिए काफी "समृद्ध शब्दावली" है.

यूनुस ने यह भी कहा कि उनके देश में चुनाव पारदर्शी तरीके से नहीं हुए थे और भारत ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा और इसके लिए "हम भारत को माफ नहीं कर सकते." भारत ने यूनुस पर या उनके बयानों पर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है. बांग्लादेश में भारत की पूर्व उच्चायुक्त वीना सीकरी ने न्यू इंडियन एक्सप्रेस अखबार को बताया कि भारत और कई देशों ने इन चुनावों में अपने आब्जर्वर भेजे थे और उनमें से किसी को भी चुनावी प्रक्रिया में कोई कमी नजर नहीं आई.

adani

एक मज़बूत आत्मनिर्भर भारत की ओर

आइए हम सब मिलकर ऐसा राष्ट्र बनाएं जो दुनिया को प्रेरित करे। एक ऐसा राष्ट्र जहाँ सपने उड़ान भरें, नई सोच को बढ़ावा मिले और हर नागरिक प्रगति में योगदान दे। एक ऐसा राष्ट्र जहाँ समृद्धि हर कोने तक पहुँचे और एकता की भावना हम सभी को जोड़े।

इस स्वतंत्रता दिवस
विकसित भारत बनाने की शपथ लें

नरेंद्र मोदी का राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन, अमित शाह, योगी या कोई और?

▪ विकास त्रिवेदी

पान या चाय की दुकान हो, टूटी सड़क पर हिचकोले खाता टेम्पो हो या बादल छूता विमान हो. नरेंद्र मोदी के समर्थकों के बीच बीते सालों में सवाल एक ही रहा- अगर मोदी नहीं तो कौन?

पहले ये सवाल पूछा जाता था कि विपक्ष में कौन है जो मोदी की जगह ले सके, अब ये भी पूछा जाने लगा है कि बीजेपी में कौन है जो उनकी जगह ले सकता है. तीसरी बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी की उम्र अगले साल 75 को छू लेगी.

75 की उम्र के राजनीतिक मायने को समझने के लिए कुछ तारीख़ों और कुछ बयानों पर गौर करिए. मई 2024 में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से जमानत पर बाहर निकले और बीजेपी को लेकर कई दावे किए. मगर एक दावा ऐसा रहा, जिस पर अमित शाह और नरेंद्र मोदी तक को अपना पक्ष रखना पड़ा. एक बात पर गौर करें कि ये सभी बयान 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम आने से पहले के हैं. तो क्या इन चुनावी नतीजों के बाद मंथन कर रही बीजेपी में अब नए वारिस के बारे में चर्चा शुरू हो रही है? बीजेपी के अंदर नरेंद्र मोदी का वारिस कौन हो सकता है और इसमें आरएसएस यानी संघ की भूमिका क्या हो सकती है?

संघ की भूमिका इसलिए भी अहम है क्योंकि जानकारों के मुताबिक- जब बीजेपी कमजोर होती है, तब संघ की भूमिका पार्टी में बढ़ जाती है. ये सवाल तब और अहम हो जाते हैं जब कई राजनीतिक जानकारों और घटनाक्रमों ने इन अटकलों को हवा दी है कि योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच राजनीतिक रस्साकशी चल रही है. 2014 में जब नरेंद्र मोदी पीएम बने तो लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे शीर्ष नेताओं को संसदीय बोर्ड या कैबिनेट में जगह नहीं दी गई. दोनों नेताओं को जगह तो मिली, मगर मार्गदर्शक मंडल में. आडवाणी तब 86 और जोशी 80 साल के थे.

जून 2016 में मध्य प्रदेश कैबिनेट विस्तार के दौरान 75 पार बाबूलाल गौर और सरताज सिंह को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, इसी तरह 80 पार पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन को भी कोई ज़िम्मेदारी नहीं दी गई, हिमाचल के दिग्गज नेता शांता कुमार भी इसी तरह किनारे हो गए.

अमित शाह ने तब कहा था, "पार्टी में न तो कोई ऐसा नियम है और न ही परंपरा कि 75 साल की आयु पार कर चुके नेताओं को चुनाव लड़ने की अनुमति न दी जाए".

कर्नाटक के येदियुरप्पा इस मामले में एक मिसाल थे जो 80 पार होने के बाद भी राज्य में बीजेपी की कमान संभाल रहे थे. 2019 के लोकसभा चुनाव में 91 साल के आडवाणी और 86 साल के जोशी को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया था. अप्रैल 2019 में द वीक को दिए इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा था, ''75 साल से ऊपर के किसी को टिकट नहीं दिया गया. ये पार्टी का फ़ैसला है.''

एक दूसरे पुराने वीडियो में शाह कहते दिखते हैं- "75 साल से ऊपर के नेताओं को जिम्मेदारी नहीं देने का फैसला हुआ है." हालांकि अतीत में कलराज मिश्र, नजमा हेपतुल्ला और अब जीतन राम मांझी 75 की उम्र पार करने के बाद भी मोदी कैबिनेट में जगह बनाने में सफल रहे. इनमें मांझी बीजेपी के नहीं हैं बल्कि उनकी पार्टी सत्ताधारी गठबंधन का हिस्सा है.

75 पार का नियम मोदी ख़ुद मानेंगे?

कभी मोदी के चुनावी रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर ने एक इंटरव्यू में कहा- "ये नियम बनाया तो मोदी जी ने ही है, तो ये उन पर है कि वो इस नियम को मानेंगे या नहीं?" संघ और बीजेपी की विचारधारा के समर्थक डॉ. सुवोकमल दत्ता कहते हैं, "75 साल उम्र होने के बाद ये प्रधानमंत्री जी के ऊपर है कि वो इस पर विचार करना चाहते हैं या नहीं. मान लीजिए कि अगर स्वेच्छा से वो सोचते हैं कि उनको अवकाश लेना चाहिए तो ये उनकी निजी सोच होगी. इसमें संगठन की तरफ से मेरा मानना है या विचारधारा की तरफ से किसी तरह का प्रेशर नहीं है." बीजेपी, संघ, अटल बिहारी वाजपेयी और योगी आदित्यनाथ पर वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी किताबें लिख चुके हैं.

विजय त्रिवेदी ने कहा, "75 की उम्र होने पर मोदी अपना कार्यकाल पूरा ना करें या संघ भी किसी और को चाह रहा हो, ऐसा नहीं लगता."

वरिष्ठ पत्रकार राकेश मोहन चतुर्वेदी कहते हैं, "नरेंद्र मोदी अभी काफी एक्टिव हैं. लगता है कि 2029 तक कंट्रोल नरेंद्र मोदी के हाथ में ही रहेगा."

मगर राजनीति अनिश्चितता से भरी होती है. ख़ास तौर पर बीजेपी और संघ के मामले में किसी

भी चीज की तैयारी बहुत पहले से चालू हो चुकी होती है.

'संघम् शरणम् गच्छामि' किताब के लेखक विजय त्रिवेदी कहते हैं, "नंबर वन के लिए लड़ाई तो जारी नहीं है. मुझे लगता है कि खोज शुरू हो गई होगी. संघ को जो हम समझते हैं वे दूरगामी निर्णयों, नीतियों पर भरोसा करते हैं. एक लंबे समय तक के लिए क्या कार्य-योजना होगी, इस पर वो लगे रहते हैं. ज़ाहिर है, बीजेपी में पीएम मोदी के अलावा दूसरे नेतृत्व की तलाश भी संघ कर रहा होगा."

तो क्या संघ ने वाक़ई तैयारी शुरू कर दी है और यहां ये समझना ज़रूरी है कि बीते 10 सालों में नरेंद्र मोदी और संघ का रिश्ता कैसा रहा है.

"वो आसमान में जितना चाहे ऊँची छलांग लगा लें, पर आना तो उन्हें धरती पर ही पड़ेगा." ये बात आरएसएस के दूसरे सरसंघचालक माधवराव गोलवलकर ने उन स्वयंसेवकों के लिए कही थी, जो नवगठित राजनीतिक दल जनसंघ में चले गए थे. जनसंघ की जगह ही भारतीय जनता पार्टी 1980 के अप्रैल महीने में सामने आई.

गोलवलकर के इस बयान को कई दशक बीत चुके हैं मगर संघ अपने नेताओं को 'आसमान से धरती' पर लाने के कई उदाहरण अतीत में पेश कर चुका है.

बलराज मधोक, जसवंत सिंह, लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी, ऐसे ही कुछ उदाहरण हैं. कहा जाता है कि जब ये बड़े नेता बोझ बनने लगे तो संघ ने नीचे लाने में देर नहीं की.

संघ का ये रुख़ अब भी ऐसा ही नज़र आता है. हाल के दिनों में संघ प्रमुख मोहन भागवत के दो बयानों पर गौर कीजिए.

मोहन भागवत के ये दोनों बयान लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद आए हैं.

इन बयानों में कहीं भी पीएम मोदी का नाम नहीं लिया गया है, संघ की ओर से आने वाले संदेश परंपरागत तौर पर ऐसे ही होते हैं जिनके बारे में दावे से नहीं कहा जा सकता कि वे किसके बारे में हैं, लेकिन ये भी कहना कठिन है कि इन बयानों का पीएम मोदी से कोई ताल्लुक नहीं है.

संघ से जुड़े कई लोगों और जानकारों का कहना है कि इन चुनावों में संघ ने बीजेपी के लिए वैसे काम नहीं किया, जैसा पहले संघ किया करता रहा है.

संघ का सबसे अहम काम है मतदाताओं के बीच ऐसी राय और माहौल बनाना जो बीजेपी के हक़ में जाए. ये संघ ही था जिसकी सहमति के साथ नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की रेस में साल 2013 में ख़ुद को आगे कर पाए थे. फिर ऐसा क्या हुआ कि संघ प्रमुख के बयानों में कुछ लोगों ने नरेंद्र मोदी के लिए संकेत देखे और दूरियों की अटकलें तेज हुईं. 2024 के लोकसभा चुनाव में संघ ने 2019 या 2014 जितनी मदद बीजेपी की क्यों नहीं की?

मई 2024 में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 'इंडियन एक्सप्रेस' को दिए इंटरव्यू में कहा, "शुरू में हम अक्षम होंगे, थोड़ा कम होंगे. आरएसएस की ज़रूरत पड़ती थी. आज हम बढ़ गए हैं. सक्षम हैं तो बीजेपी अपने-आपको चलाती है."

जानकारों का कहना है कि नड्डा के इस बयान से संघ में काफ़ी नाराज़गी देखने को मिली.

एक संपादक ने कहा, "नड्डा के बयान से इस बार संघ में नाराज़गी थी. चुनाव के दौरान होने वाले प्रशिक्षण शिविर को भी इस बार नहीं टाला गया. किसी भी संघ वाले से बात करेंगे तो वो बताएंगे कि वो ना के बराबर निकले. हाँ, उन्होंने मध्य प्रदेश में जमकर मेहनत की क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने हमेशा आदर-सत्कार किया. वहां नतीजे भी दिखे." मगर नाराज़गी सिर्फ़ इतनी भर नहीं है.

सात जून 2024 को नीतीश कुमार ने पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में कहा था- हमारी पार्टी जेडीयू बीजेपी संसदीय दल के नेता नरेंद्र मोदी को भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देती है.

नीतीश जिस संसदीय दल के नेता होने की बात मोदी के लिए कह रहे थे, क्या बीजेपी संसदीय दल की वो बैठक इस बार हुई?

बीजेपी-संघ को कवर करने वाले एक वरिष्ठ पत्रकार ने बातचीत में दावा किया, "चार जून की शाम बीजेपी संगठन के एक शीर्ष नेता और एक वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री दिल्ली में संघ के दफ्तर मिलने गए. संघ की ओर से कहा गया कि आप संसदीय दल की बैठक बुलाकर अपना नेता चुन लीजिए. ये बात संघ ने बहुत हल्के से कही. इस बात को जब आगे बताया गया तो इशारे को समझ लिया गया.'' इसके बाद बीजेपी संसदीय दल की बैठक नहीं बुलाई गई बल्कि एनडीए की बैठक हुई.

बीजेपी की वेबसाइट पर भी 2024 चुनावी नतीजे आने के बाद बीजेपी संसदीय दल नहीं, एनडीए की बैठक से जुड़ी प्रेस रिलीज़ जारी की गई. वहीं, 2019 में 303 सीटें जीतने के बाद चुनावी नतीजों के अगले दिन 24 मई को बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई थी न कि एनडीए की बैठक.

सूत्रों के किए दावे के मुताबिक, ''संघ के लोगों का अनौपचारिक रूप से ये कहना रहता है कि 240 सीटों में से 140 सांसद हमारे हैं. अगर बीजेपी की बैठक होती तो उसमें ये शायद ना चुने जाते इसलिए इन्होंने वो बैठक ही नहीं बुलाई. अगले दिन चंद्रबाबू नायडू और नीतीश को बुलाकर पत्र वगैरह लेकर एनडीए का मामला शुरू कर दिया. ये चीज़ भी संघ को अच्छी नहीं लगी कि आपने अपने आपको थोप दिया."

संघ की समझ रखने वाले लोगों की मानें तो आरएसएस व्यक्ति से ज़्यादा विचार या संगठन को महत्व देता है.

'द आरएसएस- आइकन्स ऑफ इंडियन राइट' किताब के लेखक और वरिष्ठ पत्रकार नीलांजन मुखोपाध्याय ने कहा, "एक चीज़ जो साफ़ है कि मोदी जी से नाराज़गी दिख रही है. संघ के झुकाव से पहले ये अहम है कि जो पीछे से हाथ रखा हुआ था, वो हटता दिख रहा है. ज़्यादा बड़ी खबर ये है. संघ मोदी का नाम लिए बगैर आलोचना कर रहा है."

लेकिन ऐसा मानना सही नहीं होगा कि मोदी और संघ के बीच दूरी बहुत बढ़ गई हो.

2024 चुनाव प्रचार के दौरान 10 साल में पहली बार मोदी के नागपुर में रात बिताने की भी खबरें आईं.

मुखोपाध्याय कहते हैं, "व्यक्ति को संगठन से ज़्यादा महत्व देना, पूरे मोदी कल्ट का प्रमोशन नाराज़गी का एक बड़ा कारण था."

जेपी नड्डा मोदी और शाह के आदमी माने जाते हैं. ऐसे में नड्डा के सक्षम होने वाले बयान को भी गंभीरता से लिया गया और इसे उनका पूरी तरह निजी बयान नहीं माना गया.

हालांकि जुलाई 2024 में बीजेपी की ओर से संघ के साथ रिश्तों में मिठास घोलने की कोशिश भी होती दिखी. मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के संघ का सदस्य होने पर लगे पांच दशक पुराने प्रतिबंध को हटा दिया. संघ-बीजेपी से जुड़े सूत्रों ने बताया, "बीजेपी दिखाना चाहती है कि कम सीटें आने से कुछ नहीं बदला. न कोई मंत्री बदला, न स्पीकर बदला, न अध्यक्ष बदले मगर बीजेपी जानती है कि संघ नाराज़ है. बीजेपी ने बिना पूरा झुके संघ को थोड़ा पुचकार दिया है."

संघ के प्रवक्ता सुनील आंबेकर ने सरकार के कदम की तारीफ भी की. मगर संभवतः संघ की नाराजगी इतनी ज्यादा थी कि 9 जुलाई के जारी इस आदेश के बाद भागवत ने 18 जुलाई को सुपरमैन और भगवान वाला बयान जारी किया.

मुखोपाध्याय कहते हैं, "इस बैन को हटाने के बाद भागवत ने जो बयान दिया, उससे लगता है कि मोदी जी को जो लाभ मिलना चाहिए था, मिला नहीं है. संघ के बयानों को ध्यान से देखते रहने की ज़रूरत है. देखना ये

भी चाहिए कि आलोचना कब किसी और को बैठाने के खुले निमंत्रण के तौर पर बदल जाती है."

एक तरफ़ संघ की ओर से ऐसे इशारे आना कि वे नरेंद्र मोदी से नाराज़ हैं, दूसरी ओर देश के राष्ट्रीय राजनीतिक मंच पर राहुल गांधी, अखिलेश यादव जैसे नेताओं का उभरना. फिर मोदी की बढ़ती उम्र का तकाज़ा, जनता का बदलता रुझान और सहयोगियों के सहारे चलती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार. इन वजहों के बारे में जानकारों का कहना है कि अभी हाल फिलहाल मोदी को हटाने जैसा तो कुछ नहीं होगा, मगर अगले चेहरे की तलाश, तैयारी और तकरारें शुरू हो चुकी हैं.

बीते दिनों यूपी में योगी आदित्यनाथ को लेकर जैसी अटकलें लगाई गईं, उससे इस बात को और मजबूती मिली है. यूपी में बीजेपी के एक विधायक ने कहा, "आज की तारीख में चौराहे पर बैठे आदमी को भी पता है कि बाबा (योगी) कोई काम करते हैं तो दिल्ली से नंबर-2 (शाह) डिस्टर्ब कर देते हैं."

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर डॉ पंकज कुमार ने कहा था-''अमित शाह भी ताक में हैं कि कैसे योगी को हटाया जाए. उनको सही मौका नहीं मिल पा रहा. अमित शाह की प्रबंधन की शक्तियां होंगी लेकिन जनता की नज़र में शाह कहीं खरे नहीं उतरते.''

बीजेपी पर नज़र रखने वाले एक वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं, ''बीजेपी जिन वोटर्स के बीच पसंद की जाती है, वहां मोदी के बाद योगी ही हैं. न सिर्फ़ यूपी बल्कि दूसरे राज्यों में भी. योगी की अपील अमित शाह से ज़्यादा है. ये बात योगी को भी पता है.'' योगी आदित्यनाथ बीजेपी के स्टार प्रचारकों में शामिल हैं. नाथ संप्रदाय के अहम गोरखधाम मठ के महंत होने के कारण भी योगी की देश के अलग-अलग हिस्सों में लोकप्रियता है.

संघ के प्रति झुकाव रखने वाले डॉ. सुर्वोकमल दत्ता कहते हैं, "किसी भी गतिशील पार्टी में इसको लड़ाई नहीं, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कहते हैं. ये होना जरूरी भी है और सकारात्मक होता है."

---योगी बनाम शाह?

हमने संघ, बीजेपी, सूत्रों और कई वरिष्ठ पत्रकारों से बात की. ज्यादातर का कहना है कि अभी जो लड़ाई है, वो योगी और शाह के बीच ही दिखती है. ऐसे में संघ किस ओर नज़र आता है?

एक दैनिक अखबार के संपादक ने कहा- ''संघ योगी के साथ है. नंबर-2 चाहते हैं कि योगी हट जाए तो लड़ाई ही ख़त्म हो जाएगी. पर संघ का हाथ योगी के साथ इतना मजबूती के साथ है कि उनका हटना कुछ मुश्किल है.'' बीजेपी से जुड़े सूत्र बताते हैं, ''मोदी चाहते हैं कि अमित शाह ही मेरी जगह लें. इधर से शाह योगी के काम में दखल देते हैं. उधर योगी इनके अपनों को झटका देते हैं.'' वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को लेकर खींचतान. यूपी में स्मार्ट मीटर की रेस में अदानी का होना और उसका टेंडर का रद्द होना. ये कुछ ऐसे वाकये हैं, जिनके जरिए योगी बनाम मोदी सरकार की दूरियों की ओर इशारा किया जाता है.

वरिष्ठ पत्रकार राकेश मोहन चतुर्वेदी कहते हैं, ''अभी जो नाम हैं, उनमें योगी और शाह का नाम आता है. योगी हिंदुत्व का चेहरा हैं. वहीं मोदी की योजनाओं को लागू करने में शाह की अहम भूमिका रही है. ''

नितिन गडकरी को 2009 में बीजेपी अध्यक्ष बनाना हो, योगी को यूपी में सीएम बनाना हो या जून 2005 में मोहम्मद अली जिन्ना को सेक्यूलर बताने के बाद आडवाणी से बीजेपी अध्यक्ष की कुर्सी छीनना. बीजेपी से जुड़े बड़े फैसलों के पीछे संघ रहा है.

योगी और शाह का जिक्र करते हुए पत्रकार विजय त्रिवेदी कहते हैं, ''मुझे लगता है कि जब भी फ़ैसला होगा वो संघ की सहमति से दिशा-निर्देश और आपसी बातचीत से तय हो सकता है.''

ऐसे में अब सवाल ये है कि अगर योगी बनाम शाह की अटकलों को सही माना जाए तो संघ का झुकाव किस ओर होगा? संघ आधिकारिक या सार्वजनिक तौर पर इन मुद्दों पर टिप्पणी नहीं करता है.

संघ में अहम पद की ज़िम्मेदारी संभाल रहे एक शख़्स ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, ''जब समय आएगा जिसके बारे में सहमति बनेगी, बीजेपी तय कर लेगी. इन सारे विषय में उस समय बीजेपी को कोई सहयोग चाहिए होगा तो संघ के अधिकारी उनसे संपर्क में रहते हैं. इस विषय पर वो बात रखेंगे. जो सुझाव देना होगा, वो सुझाव देंगे. अंतिम निर्णय बीजेपी को करना होगा.''

वो बोले, ''हमें नहीं लगता कि कोई परिवर्तन हो रहा है. बातचीत लोग करते रहेंगे, अपने अंदाजे लगाते रहेंगे.'' इसी अंदाज़े के बारे में हमने संघ समर्थक डॉ. सुर्वोकमल दत्ता से पूछा.

डॉ. सुर्वोकमल दत्ता कहते हैं, ''मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो मैं समझता हूं कि महंत योगी आदित्यनाथ जी हैं. उनके साथ-साथ हिमंत बिस्वा सरमा, शिवराज सिंह चौहान, पीयूष गोयल, अनुराग ठाकुर जैसे कई नेता हैं...' आपने कई नाम लिए, मगर अमित शाह का नाम नहीं लिया?

इस सवाल पर डॉ दत्ता जवाब देते हैं, ''मैं समझता हूं कि अमित शाह जी मोदी जी के बाद दूसरे नंबर पर हैं, कहीं न कहीं पूरे देश में उनकी पहचान है. उनकी छवि, यूएसपी बहुत हार्डकोर नेता की है. उनको सेकेंड लाइन में गिनना उचित नहीं है.''अमित शाह की बीजेपी संगठन के अंदर मजबूत पकड़ है.

सूत्रों के मुताबिक, शाह का मानना है कि संगठन में ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोग ही हो जाएं ताकि अगर कल को जरूरत पड़ती है तो पार्टी में ज़्यादा लोग शाह के पक्ष में बोलें. शाह और मोदी को अलग-अलग नहीं देखा जा सकता. दोनों पुराने साथी हैं. हालांकि शाह के बारे में जानकारों का कहना है कि उनके साथ जाति या लोकप्रियता वाले फैक्टर नहीं हैं, जो योगी के साथ हैं.

वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह ने कहा, ''योगी आदित्यनाथ संगठन से उठे व्यक्ति नहीं है. उनका बीजेपी में हस्तक्षेप या भूमिका कभी नहीं रही है. संगठन में जो पदाधिकारी हैं, वो योगी को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं.''

योगी आदित्यनाथ के पीछे संघ की भूमिका पर अतुल चंद्रा और शरत प्रधान अपनी किताब में विस्तार से लिखते हैं. अपनी किताब 'योगी आदित्यनाथ' में वो लिखते हैं- हिंदुत्व की मुखर और मजबूत आवाज होने के कारण योगी आदित्यनाथ को संघ प्रमुख मोहन भागवत का आशीर्वाद हासिल है. किताब के मुताबिक़, ''2017 में भागवत ने ही मोदी को मनाया था कि यूपी में आईआईटी ग्रेजुएट नेता मनोज सिन्हा से बेहतर राजनीतिक दाव भगवाधारी महंत योगी आदित्यनाथ होंगे. इससे पार्टी का हिंदुत्व का एजेंडा यूपी में साफ हो सकेगा.'' योगी यूपी और भारत के हिंदू राष्ट्र होने या बनाए जाने को लेकर बयान देते रहे हैं.

'माया, मोदी, आज़ाद' किताब के लेखक, राजनीतिक मामलों की जानकार सुधा पाई और सज्जन कुमार ने 2017 में एक लेख लिखा था. इस लेख के मुताबिक़, ''बीजेपी-संघ का लक्ष्य सिर्फ़ चुनाव जीतना नहीं है बल्कि भारत को ज्यादा हिंदू बनाना है. आइडिया है कि बड़े दंगों के बिना आम लोगों की नज़र में हिंदुत्व को स्वीकार्य बनाया जाए और मुसलमानों को दूसरे की तरह पेश किया जाए. योगी आदित्यनाथ ये काम सफलतापूर्वक करते रहे हैं. ऐसे में संघ ने योगी को इस मामले में एक सफल व्यक्ति माना.''

15 अगस्त

आप सभी को

स्वतंत्रता दिवस की

हार्दिक शुभकामनाएं।

विजयी विश्व तिरंगा प्यारा,
झंडा ऊंचा रहे हमारा

शशांक राज

प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा, झारखण्ड

विधानसभा चुनाव 2024:हरियाणा में एक और जम्मू-कश्मीर में तीन चरणों में चुनाव

चुनाव आयोग ने शुक्रवार को हरियाणा और जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है. चुनाव आयोग ने बताया कि जम्मू कश्मीर में तीन चरणों में- 18 सितंबर, 25 सितम्बर और एक अक्तूबर को मतदान होगा.

हरियाणा में एक अक्तूबर को मतदान होगा. दोनों राज्यों में मतगणना चार अक्तूबर को होगी.

हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल 3 नवंबर को समाप्त हो रहा है. जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने का आदेश दिया था.

मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि जम्मू कश्मीर में 90 विधानसभा सीटें होंगी. ये परिसीमन के बाद की सीटें हैं. चुनाव आयोग ने बताया कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में इस बार 3 सीटें बढ़ाई गई हैं. पिछली बार जम्मू कश्मीर विधानसभा में 87 सीटें थीं. मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा, ''जम्मू कश्मीर की 90 सीटों में से 74 सामान्य हैं. वहीं अनुसूचित जनजाति के 9 और अनुसूचित जाति के लिए 7 सीटें आरक्षित की गई हैं.'' जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया था. जम्मू-कश्मीर और लेह-लद्दाख.

मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने जम्मू कश्मीर की तारीख़ों का एलान करते हुए बताया कि यहां कुल 87.09 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. उन्होंने लोकसभा चुनावों के दौरान मतदाताओं के उत्साहपूर्वक अपने मताधिकार के इस्तेमाल का ज़िक्र किया और उम्मीद जताई कि मतदाता इस बार भी ऐसा करेंगे. उन्होंने कहा, '19 अगस्त को अमरनाथ यात्रा जैसे ही ख़त्म होगी 20 अगस्त को मतदाता सूची प्रकाशित कर दी जाएगी. हमने मौसम और सुरक्षा का ध्यान रखते हुए ऐसा किया है.'

राजीव कुमार ने जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए अपनी लिखी एक कविता भी पढ़ी, 'लंबी कतारों में छिपी है बदलते सूरते हाल, रोशन उम्मीदें अब खुद करेंगी गोया अपनी तकदीरे बयानी, जम्हूरियत के जश्न में आपकी शिरकत दुनिया देखेगी नापाक इरादों के शिकस्त की कहानी.'

उधर हरियाणा एक अक्तूबर को मतदान होगा. आयोग के अनुसार, हरियाणा में 10,321 मतदाता सौ वर्ष से ऊपर के हैं. जबकि 2.5 लाख मतदाताओं की उम्र 85 वर्ष से ऊपर है. इन मतदाताओं को विशेष सुविधा देते हुए उन्हें घर से मतदान की अनुमति दी जाएगी.

जब भी 85 वर्ष से अधिक मतदाता का घर से मतदान होता है तो राजनीतिक पार्टी के एजेंट वहां मौजूद रह सकते हैं और इसकी वीडियोग्राफी भी होती रहेगी. हरियाणा के 22 जिलों की 90 विधानसभा सीटों में 73 सामान्य और अनुसूचित जनजाति आरक्षित 17 सीटों पर चुनाव होंगे. यहां कुल 2.01 करोड़ मतदाता

चार अक्तूबर को होगी मतगणना

अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. हरियाणा का मतदाता सूची 27 अगस्त को जारी हो जाएगी.

राजीव कुमार ने कहा कि मतदाता सूची को अंतिम रूप दिया जा चुका है, बावजूद हरियाणा और जम्मू कश्मीर में नामांकन से पहले अगर कोई व्यक्ति छूट गया कोई व्यक्ति अपना पंजीकरण करा सकता है. चुनाव आयोग के अनुसार, पहले चरण की अधिसूचना 28 अगस्त को, दूसरे चरण का 29 अगस्त को और तीसरे चरण का 5 सितम्बर को अधिसूचना जारी होगी. इसी तरह पहले चरण के लिए 27 अगस्त, दूसरे चरण के लिए पांच सितम्बर और तीसरे चरण के लिए 12 सितंबर को नामांकन की तारीख है. जबकि नामांकन वापसी की तारीख पहले चरण के लिए 30 अगस्त, दूसरे चरण के लिए 9 सितम्बर और तीसरे चरण के लिए 17 सितम्बर है.मतदान की तारीख पहले चरण की 18 सितम्बर, दूसरे चरण की 25 सितम्बर और तीसरे चरण की एक अक्टूबर को घोषित की गई है.

दल्ली से सटे हरियाणा में 2019 विधानसभा चुनावों में कोई भी दल स्पष्ट बहुमत हासिल नहीं कर सका था. कुल 90 सीटों में से बीजेपी को 40, कांग्रेस को 31, जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) को 10, निर्दलीय पांच, इंडियन नेशनल लोकदल, हरियाणा जनहित कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल को एक-एक सीट मिली थी. स्पष्ट बहुमत ना मिलने के बावजूद बीजेपी ने निवर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में जेजेपी के गठबंधन में सरकार बनाई. हालांकि, 2024 में लोकसभा चुनावों से पहले बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री पद से हटाकर नायाब सैनी को सीएम बना दिया था. इस बदलाव के बावजूद 2019 में हरियाणा में दस लोकसभा सीटों में से दसों सीटें जीतने वाली बीजेपी को 2024 लोकसभा चुनावों में पांच सीटें गंवानी पड़ी. जेजेपी और बीजेपी गठबंधन में भी दरार पड़ गई और दुष्यंत चौटाला के अलग होने के बाद बीजेपी ने निर्दलीयों के साथ मिलकर राज्य में सरकार बनाई. आगामी विधानसभा चुनावों में हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस के बीच दिलचस्प मुकाबला हो सकता है. बीते दस सालों से राज्य में बीजेपी की सरकार है, ऐसे में पार्टी को सरकार विरोधी लहर का सामना भी करना पड़ सकता है.

5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर को मिला विशेष राज्य का संवैधानिक दर्जा समाप्त कर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया था.जम्मू-कश्मीर में पिछले विधानसभा चुनाव दिसंबर 2014 में हुए थे. हालांकि कोई भी पार्टी राज्य में बहुमत हासिल नहीं कर सकी थी. पीडीपी ने सबसे ज़्यादा 28 सीटें जीतीं थीं, बीजेपी को 25 सीटें मिलीं थीं जबकि नेशनल कांफ्रेंस ने 15 और कांग्रेस ने 12 सीटें जीतीं थीं. महबूबा मुफ़्ती ने बीजेपी के साथ गठबंधन करके सरकार तो बना ली थीं लेकिन दोनों दलों में मतभेदों के चलते ये सरकार अपने पांच साल पूरे नहीं कर सकी. महबूबा मुफ्ती ने 19 जून 2018 को इस्तीफा दे दिया था. मुफ़्ती के सरकार गिराने के बाद से राज्य में विधानसभा चुनाव नहीं हो सके और गवर्नर का शासन लगा दिया गया.

केंद्र सरकार ने जब अगस्त 2019 में जम्मू-कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा तब राज्य में गवर्नर शासन ही लागू था. तब से राज्य में बार-बार राजनीतिक दल चुनावों की मांग तो उठाते रहे, लेकिन चुनावी कार्यक्रम घोषित नहीं किया गया. अब लोकसभा चुनाव हो जाने के बाद, जम्मू-कश्मीर में विधानसभा के लिए चुनावों की घोषणा की जा रही है. हालांकि, बीते पांच सालों में जम्मू-कश्मीर में राजनीतिक गतिविधियां थम सी गईं थीं और राज्य के राजनीतिक दलों ने सरकार पर गवर्नर शासन को लंबा खींचने के आरोप भी कई बार लगाए. जम्मू-कश्मीर में इस समय कोई राजनीतिक गठबंधन भी नहीं हैं, हालांकि नेशनल कांफ्रेंस और कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर के इंडिया गठबंधन में शामिल हैं.

PNM

HAPPY

INDEPENDENCE DAY

Let's honor to martyrs for the sacrifices they made
and thank them for giving us our today.

6517966093

WWW.PNMPL.COM

विकसित छत्तीसगढ़ का संकल्प लेकर आगे बढ़ रही सरकार : विष्णु देव साय

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा भारतवर्ष को 2047 तक विकसित देश बनाने के संकल्प में छत्तीसगढ़ प्रभावी भूमिका अदा कर रहा है। हमारी सरकार विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को लेकर राज्य के चहुंमुखी विकास के लिए नई-नई योजनाएं तैयार कर रही है। उन्होंने राज्य की जनता को 78वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमारे पूर्वजों के कठिन संघर्ष और बलिदान से हमें आजादी मिली है। आजादी के लिए हमारे पुरखों ने अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरूद्ध लंबा संघर्ष किया। उनके बलिदान और संघर्षों के फलस्वरूप मिली आजादी को हमें अक्षुण्ण बनाए रखना है। लोकतांत्रिक ताकतों को मजबूत बनाना है। मुख्यमंत्री श्री साय राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस मुख्य समारोह में ध्वजारोहण के बाद प्रदेशवासियों को सम्बोधित कर रहे थे।

देश के अन्य हिस्सों की तरह छत्तीसगढ़ में शहीद गेंद सिंह, शहीद धुरवा राव, शहीद यादव राव, शहीद वेंकट राव, वीर गुंडाधुर, शहीद डेबरी धुर, शहीद आयतु माहरा, शहीद वीर नारायण सिंह जैसे हमारे अनेक ऐतिहासिक नायकों ने अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेकने के लिए अदम्य साहस का परिचय देते हुए जनमानस में स्वाधीनता की अलख जगायी। आज जिस स्वतंत्रता का उपभोग कर रहे हैं, वह हमारे पुरखों के बलिदान का प्रतिफल है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान आज लोकतंत्र को आगे बढ़ने की राह दिखा रहा है। यह हमारे लिए एक प्रकाश स्तंभ है। बरसों पहले बाबा गुरु घासीदास जी ने समतामूलक समाज का आदर्श हम सबके सामने रखा था, जो बाबा साहेब द्वारा निर्मित संविधान में फलीभूत हुआ। उनके संविधान में कबीर की वाणी का सार भी है, जो भारत के नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ-साथ समानता प्रदान करती है।

अब बस्तर तीव्र विकास के लिए है तैयार : मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि नक्सलवादी घटनाओं से निपटने के लिए अनुसंधान और अभियोजन की कार्रवाई और भी प्रभावी रूप से हो सके, इसके लिए हमने राज्य अन्वेषण एजेंसी (एसआईए) का गठन किया है। बस्तर की जनता नक्सलियों से त्रस्त हो चुकी है और विकास के मार्ग पर सरपट दौड़ने को तैयार है। उन्होंने कहा कि अन्दरूनी क्षेत्रों में नये कैंपों का विस्तार कर लोगों को आतंक से मुक्ति देने के साथ ही इन क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने का काम भी युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। इसके लिए हमने ''नियद नेल्लानार'' योजना शुरू की है। इस शब्द का अर्थ होता है -''आपका अच्छा गांव''। विशेष पिछड़ी जनजातियों के हितग्राहियों के लिए आरंभ की गई ''पीएम जनमन योजना'' की तरह इस

योजना से कैंपों के निकट पांच कि.मी. की परिधि के गांवों में 17 विभागों की 53 हितग्राही मूलक योजनाओं एवं 28 सामुदायिक सुविधाओं का लाभ लोगों को दिया जा रहा है। इन गांवों में पहली बार लोगों के आयुष्मान कार्ड बने हैं। वे शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी सरकार की लोकहितकारी योजनाओं का लाभ अब उठा रहे हैं। उनके जीवन में सुशासन का नया सवेरा आया है।

प्रदेश में रिकॉर्ड धान खरीदी : मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमें अपने जवानों के साथ अपने किसानों पर भी गर्व है। उनके श्रम से छत्तीसगढ़ महतारी का धान का कटोरा भरा-पूरा रहता है। प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी के अनुरूप हमने अन्नदाताओं की सुख-समृद्धि को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा है। पूर्व प्रधानमंत्री और हमारे प्रेरणा पुंज अटल जी के जन्मदिन ''सुशासन दिवस'' के अवसर पर हमने राज्य के 13 लाख किसानों के बैंक खाते में 3716 करोड़ रुपये का बकाया धान बोनस अंतरित किया। हमने अपने वायदों को पूरा करते हुए किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से और 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदी की। प्रदेश में ''रिकॉर्ड'' 145 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की गई।

खेती-किसानी में लौटी रौनक : मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि किसानों को समर्थन मूल्य की 32 हजार करोड़ रुपए की राशि के साथ ही कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत प्रदेश के 24 लाख 75 हजार किसानों को अंतर की राशि 13 हजार 320 करोड़ रुपये अंतरित किए गए। इस प्रकार हमारे अन्नदाताओं के खाते में सरकार ने धान खरीदी और बकाया बोनस मिलाकर लगभग 49 हजार करोड़ रुपए अंतरित किए। भूमिहीन किसानों को हमने दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना के अंतर्गत 10 हजार रुपए वार्षिक सहायता राशि देने का निर्णय लिया है। प्रदेश में कृषि हितैषी नीतियों की वजह से खेती-किसानी में रौनक लौट आई है और किसानों के चेहरों पर मुस्कान नजर आ रही है। आज हमारे गांव आर्थिक रूप से संपन्न नजर आते हैं। एक लोककल्याणकारी सरकार के लिए इससे बढ़कर संतोष की बात और कुछ नहीं हो सकती।

प्रदेश के विकास में मातृशक्ति की अहम भूमिका: मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ को गढ़ने और सँवारने में मातृशक्ति की अहम भूमिका है। हम उनके योगदान का वंदन करते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में तीज-त्योहार की परंपरा है। तीजा के मौके पर भाई अपनी बहनों को भेंट देते हैं। प्रदेश की माताओं-बहनों को ''महतारी वंदन योजना'' के रूप में यही भेंट हम प्रदान कर रहे हैं। 10 मार्च, 2024 के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअल समारोह में 70 लाख माताओं-बहनों के खाते में महतारी वंदन योजना की पहली किस्त के रूप में एक-एक हजार रुपए की राशि अंतरित की। अब तक इस योजना की छह किश्त जारी की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि हमारी माताएं-बहनें इससे आर्थिक रूप से सक्षम व आत्मनिर्भर हुई हैं। वे इस राशि का उपयोग अपनी इच्छा अनुसार बच्चों की पढ़ाई एवं घर के बजट को व्यवस्थित करने में कर रही हैं, जिससे उन्हें आर्थिक संबल मिल रहा है। जब हम बेटियों को मजबूत करते हैं तो पूरा परिवार मजबूत होता है और मजबूत परिवार से ही मजबूत समाज और मजबूत राष्ट्र का निर्माण होता है। महिलाओं के आर्थिक सामाजिक सशक्तीकरण से निश्चित ही विकसित छत्तीसगढ़ की आधारशिला मजबूत हो रही है।

समाज के सबसे आखिरी व्यक्ति का उत्थान : मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने हमारे समक्ष अंत्योदय के लिए कार्य करने का आदर्श रखा है। समाज के सबसे आखिरी व्यक्ति के उत्थान और विकास को सुनिश्चित करने के इसी लक्ष्य के अनुरूप हम अनथक कार्य कर रहे हैं। अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशनकार्डधारी 68 लाख परिवारों को अगले पांच सालों तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरण का निर्णय हमारी सरकार द्वारा लिया गया है। आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

SECL

South Eastern Coalfields Ltd.

78वें स्वतंत्रता दिवस

की हार्दिक शुभकामनाएँ

78वें स्वतंत्रता दिवस की समस्त कोयलांचलवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ।

आइये इस पावन पर्व पर यह संकल्प लें कि हम सभी एक लक्ष्य, एक दृष्टि, एक मति और एक गति के साथ, विकसित भारत के सपने को साकार करने में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देंगे।

(डॉ. प्रेम सागर मिश्रा)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
एसईसीएल

एसईसीएल : भारत को एक विकसित एवं ऊर्जा सम्पन्न राष्ट्र बनाने का लिया है हमने संकल्प

- एसईसीएल की दो खदानों गेवरा एवं कुसमुंडा ने विश्व की टॉप 10 खदानों में दूसरा एवं चौथा स्थान पाकर राष्ट्र को विश्व पटल पर गौरवान्वित किया है और राष्ट्र की ऊर्जा की बुनियाद को और मजबूत किया है।
- राष्ट्र की ऊर्जा आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए एसईसीएल दृढ़ संकल्पित है। एसईसीएल ने कोयला उत्पादन में वित्त वर्ष 22-23 में 25 मिलियन टन की रिकॉर्ड बढ़ोत्तरी के ऊपर वित्त वर्ष 23-24 में 20 मिलियन टन की बढ़ोत्तरी हासिल करते हुए अपने इतिहास का सर्वाधिक 187 एमटी कोयला उत्पादन दर्ज किया है।
- कोयलांचल के भू-स्वामियों के त्वरित रोजगार एवं समुचित बसाहट के लिए एसईसीएल निरंतर प्रयासरत है। कंपनी ने भूमि अधिग्रहण की देयताओं में सकारात्मक बदलाव किए हैं। पिछले 2 वर्षों में एसईसीएल ने रिकॉर्ड 1500 से अधिक भू-स्वामियों को रोजगार स्वीकृति प्रदान की है।
- एक हरित कोयलांचल के लिए एसईसीएल बड़े स्तर पर वृक्षारोपण कर रहा है। पिछले 2 वर्षों में एसईसीएल ने अपने संचालन राज्यों में 19 लाख से अधिक पौधे लगाए हैं। साथ ही वृक्षारोपण की जापानी तकनीक "मियावाकी" को भी प्रयोग में लाने की शुरुआत हुई है।
- एसईसीएल द्वारा बंद हुई खदानों को ईको-पार्क के रूप में विकसित कर रमणीक पर्यटन स्थल में बदला जा रहा है। कंपनी हसदेव क्षेत्र में अनन्या वाटिका एवं बिश्रामपुर क्षेत्र में केनापारा पर्यटन स्थलों को विकसित कर चुकी है जो स्थानीय लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुके हैं। साथ ही एसईसीएल द्वारा कोरबा जिले में तीन और नए पार्क बनाने की योजना पर भी काम किया जा रहा है।
- एसईसीएल ने आने वाले वर्षों में एक नेट-पॉजिटिव कंपनी बनने का लक्ष्य साधा है। इसके तहत एसईसीएल के विभिन्न संचालन क्षेत्रों में रूफटॉप एवं ग्राउंड माउंटेड ग्रिड कनेक्टेड सोलर परियोजनाओं को विकसित किया जा रहा है। एसईसीएल के भटगांव क्षेत्र में 20 मेगावाट की ग्राउंड माउंटेड ग्रिड कनेक्टेड सोलर परियोजना से उत्पादन शुरू हो चुका है वहीं बिश्रामपुर क्षेत्र में इसी क्षमता के एक और परियोजना के जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। कंपनी ने मुख्यालय एवं विभिन्न संचालन क्षेत्रों में रूफ-टॉप/फ्लोटिंग सोलर परियोजनाओं पर काम शुरू कर दिया है।
- "एसईसीएल के सुश्रुत" योजना के तहत एसईसीएल कोयलांचल के बच्चों के डॉक्टर बनने के सपने को पंख दे रही है। योजना के तहत कंपनी आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के 40 बच्चों को निशुल्क आवासीय नीट मेडिकल कोचिंग प्रदान कर रही है।
- सीएसआर के जरिये हमारा प्रयास कोयलांचल के कोने-कोने को विकास से समृद्ध करना है। इसके अंतर्गत एसईसीएल के संचालन राज्यों में लगभग 800 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट-क्लास लगाए गए हैं जिससे इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे अध्ययन-अध्यापन की इस आधुनिक तकनीक का लाभ ले पा रहे हैं।

साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

सीपत रोड, बिलासपुर (छ.ग.) 495006

सोशल मीडिया
पर हमें लाइक और फॉलो करें

southeasterncoalfields | secl_cil | seclbilaspur | South Eastern Coalfields Limited (SECL) | seclbilaspur | SECL Media

एनसीएल ने रॉयल्टी और जीएसटी के रूप में केंद्र व राज्य के खजाने में 15,000 करोड़ रुपए दिए

नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) के अध्यक्ष-सह- प्रबंध निदेशक बी साईराम ने कहा है कि कंपनी ने अपने कुल कोयला उत्पादन का 94 प्रतिशत बिजली क्षेत्र को भेजा और वित्त वर्ष 2023-24 में रॉयल्टी और जीएसटी के रूप में केंद्र और राज्य के खजाने में 15,000 करोड़ रुपये का योगदान दिया।

एनसीएल द्वारा अपने मुख्यालय में आयोजित सिंगरौली इंडस्ट्रियल समिट 2024 को संबोधित करते हुए सीएमडी ने सिंगरौली क्षेत्र के समावेशी विकास में कंपनी के योगदान को भी रेखांकित किया। उन्होंने सिंगरौली के समग्र विकास के लिए साझा मूल्यों पर आधारित एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने के लाभों पर जोर दिया।

इस शिखर सम्मेलन का आयोजन आर्थिक विकास, सतत औद्योगिक विकास, विविधीकरण, पूर्ण औद्योगिक क्षमता का दोहन, तथा सामाजिक-आर्थिक उत्थान और क्षेत्रीय विकास के साथ रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्यों के साथ किया गया था। शिखर सम्मेलन में ऊर्जा, एल्यूमीनियम, सीमेंट, रसायन और बुनियादी ढांचे जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अवसर पैदा करने के बारे में विचार-मंथन किया गया। इसके अलावा, सिंगरौली क्षेत्र के दीर्घकालिक विकास पर एक पैनल चर्चा आयोजित की गई।

एनसीएल ने चालू वित्त वर्ष में 139 मिलियन टन कोयला उत्पादन और प्रेषण पर नज़र रख रही है। कंपनी ने 2023-24 में 136.15 मिलियन टन कोयला उत्पादन किया था, 137.63 मिलियन टन कोयला डिस्पैच किया था। एनसीएल ने पूंजीगत व्यय के रूप में 4,727 करोड़ रुपए खर्च किए थे।

बीसीसीएल) ने सीआईएल चेयरमैन को पहले डिविडेंड का चेक सौंपा

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की अनुषांगिक कंपनी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) ने अपनी मूल कंपनी को 44.43 करोड़ रुपए का पहला लाभांश दिया। बीसीसीएल द्वारा अपने संचित घाटे को खत्म करने और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 1,564 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज करने के बाद यह उपलब्धि हासिल की गई है, जिसमें 13,216 करोड़ का कारोबार हुआ है। बीसीसीएल के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक समीरन दत्ता ने एक समारोह में औपचारिक रूप से लाभांश का चेक सीआईएल चेयरमैन पीएम प्रसाद को सौंपा। 1 अगस्त को बीसीसीएल की 53वीं वार्षिक आम बैठक में लाभांश भुगतान को शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया गया था। सीएमडी दत्ता ने कंपनी के मजबूत वित्तीय प्रदर्शन और रणनीतिक प्रगति का श्रेय हाल के वर्षों में 15 प्रतिशत की लगातार वृद्धि दर को दिया।

ईसीएल सीएमडी के लिए सतीश झा के नाम की पीईएसबी ने की अनुशंसा

कोल इंडिया (सीआईएल) की अनुषांगिक कंपनी ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल) के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के पद के लिए सतीश झा के नाम की अनुशंसा की गई है। पिछले माह कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के लोक उद्यम चयन बोर्ड (पीईएसबी) ने साक्षात्कार का परिणाम जारी किया। पीईएसबी ने इसी साल 26 फरवरी को ईसीएल सीएमडी के लिए विज्ञापन जारी किया था। ईसीएल का सीएमडी बनने के लिए अलग- अलग कंपनियों से 10 अधिकारियों ने साक्षात्कार में भागीदारी की थी। लोक उद्यम चयन बोर्ड ने सतीश झा के नाम की अनुशंसा की। श्री झा वर्तमान में कोल इंडिया की अनुषांगिक कंपनी सीएमपीडीआई में निदेशक (टेक्निकल, प्रोजेक्ट एंड प्लानिंग) के पद पर कार्यरत हैं। ईसीएल के सीएमडी का प्रभार समीरन दत्ता संभाल रहे हैं। श्री दत्ता बीसीसीएल के सीएमडी हैं। उन्हें दिसम्बर, 2023 को ईसीएल के सीएमडी पद का अतिरिक्त चार्ज दिया गया था।

बीसीसीएल
BCCL
भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

(एक मिनीरत्न कम्पनी)
(कोल इण्डिया लिमिटेड की एक अनुषंगी कंपनी)

G20 भारत 2023 INDIA
वसुधैव कुटुम्बकम्
ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE

आज़ादी का अमृत महोत्सव

कोकिंग कोल से राष्ट्र के विकास को गति देता बीसीसीएल
Fueling the nation's growth with coking coal: BCCL

बीसीसीएल समय से आगे !

शिक्षा, स्वास्थ्य और सामुदायिक विकास के प्रति समर्पित

"राष्ट्र की ऊर्जा आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए सदैव प्रतिबद्ध"

कोयला भवन, कोयला नगर, धनबाद
facebook.com/BCCLofficial
twitter.com/bcclofficial
instagram.com/bccl.official

Verma Enterprises, Dhanbad, Mob 94313 14776

मोरहाबादी मैदान में मुख्यमंत्री हेमंत ने किया झंडोत्तोलन कहा राज्य की तरक्की में विरोधी ताकतें रोक रही रास्ता

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रांची के मोरहाबादी मैदान में झंडोत्तोलन किया। झंडोत्तोलन से पहले उन्होंने परेड का निरीक्षण किया। वहीं झंडोत्तोलन के बाद अपने संबोधन में उन्होंने आजादी के महत्व को बताते हुए उन तमाम लोगों को नमन किया, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपने जान की परवाह नहीं की। इस दौरान उन्होंने झारखंड के उन नायकों को भी याद किया, जिन्होंने अपना सब कुछ आजादी की लड़ाई के झोंक दिया। मंच से उन्होंने सरकार की उपलब्धियां और विकास के रास्ते पर आई परेशानियों का भी जिक्र किया। हेमंत सोरेन ने कोरोना के साथ- साथ उन विरोधी ताकतों का भी जिक्र किया जिसकी वजह से बाधाएं आई। कहा कि अगर इरादे नेक हो तो दुनिया की कोई भी ताकत झुका नहीं सकती है। मान - सम्मान के लिए संघर्ष करना परंपरा रह गई है। गरीब और असहाय अब खुद को मजबूत महसूस कर रहा है।

राज्य की विरोधी ताकतों ने विकास को रोका: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह भी कहा कि राज्य की विरोधी ताकतों ने विकास का रास्ता रोकने की पूरजोर कोशिश की पर हम आगे बढ़ते रहे। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों पर कहा कि आज हम तीन कमरों का मकान दे रहे हैं। 35 लाख लोगों को पेंशन दे रहे हैं। किसानों के ऋण माफ कर रहे हैं। इस योजना के तहत 2 लाख तक के ऋण को माफ करने का फैसला लिया है। किसानों की आय बढ़ाकर आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जा रहा है। फसल का नुकसान होने पर किसानों को आर्थिक सहायता दी जा रही है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना पहली प्राथमिकता है। इसके लिए कई योजनाएं काम कर रही है।

अपने संबोधन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा एक वक्त था जब किसी को मजदूरों की चिंता नहीं थी। अब हालात बदले हैं हमारी सरकार मजदूरों के साथ खड़ी है। कोरोना में सहायता पहुंचाने की कोशिश हुई। अभी हाल में ही कैमरून दक्षिण अफ्रीका में फंसे 27 मजदूरों को वापस लाया गया। उत्तरकाशी में टनल में फंसे मजदूरों को वापस लाया गया। युवाओं को रोजगार से जोड़ना हमारी प्राथमिकता रही।

भाषण की अहम बातें

- अब अबुआ आवास योजना के माध्यम से गरीबों को तीन कमरों का पक्का मकान दिया जा रहा है। 35 लाख जरूरतमंदों को पेंशन, 20 लाख अतिरिक्त लोगों को राशन और 57 लाख से अधिक लोगों को साल में दो बार कपड़े दिए जा रहे हैं।
- सरकार किसानों को केंद्र में रखकर झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के माध्यम से राहत दे रही है। इस योजना के माध्यम से दो लाख रुपए तक का कृषि ऋण माफ किया जाएगा।
- बिरसा हरित ग्राम योजना और मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के माध्यम से किसान की आय बढ़ाकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है।
- झारखंड राज्य फसल राहत योजना के माध्यम से फसलों के नुकसान होने की स्थिति में किसानों को क्षतिपूर्ति दी जा रही है।
- सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने पर जोर दे रही है। फूलों झानों आशीर्वाद अभियान, दीदी बाड़ी योजना, दीदी बगिया योजना के माध्यम से महिलाओं को आजीविका उपलब्ध कराया जा रहा है।
- सखी मंगल और पलाश ब्रांड के जरिए ग्रामीण महिला श्रम शक्ति को सम्मान मिला है।
- सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के माध्यम से 8 लाख से अधिक किशोरियों को पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है।
- झारखंड मुख्यमंत्री मईंयां सम्मान योजना इसी कड़ी की एक योजना है। जिसे हाल में शुरू किया गया है। इस योजना के तहत 21 वर्ष से 50 वर्ष तक की महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रुपए दिए जा रहे हैं। इसका लाभ 48 लाख महिलाओं को मिलने जा रहा है।
- राज्य सरकार 35000 पदों पर नियुक्ति करने जा रही है। जिसे अक्टूबर 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। इसमें उत्पाद सिपाही, आरक्षी, सहायक आचार्य, महिला पर्यवेक्षिका जैसे पद हैं। वहीं झारखंड लोकसभा आयोग द्वारा 342 पदों पर नियुक्ति के लिए रिजल्ट जारी किया जाएगा।
- युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना शुरू की गई है। जिसके माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना के तहत 12417 आवेदन स्वीकृत हुए हैं। जिनके लाभुकों के बीच 262 करोड़ रुपए बांटे गए हैं।

▪ युवाओं को हुनरमंद बनाने के लिए मुख्यमंत्री सारथी योजना चल रही है। राज्य में संचालित बिरसा केंद्रों में कौशल प्रशिक्षण देने के साथ-साथ युवाओं को 1000 रुपए तथा युवतियों एवं दिव्यांगजनों को 15 सौ रुपए प्रतिमाह रोजगार प्रोत्साहन भत्ता दिया जा रहा है।

▪ झारखंड सरकार राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 लागू की है। इस नियम के तहत 40 हजार रुपए तक के मासिक वेतन या मजदूरी पाने वाले पद में 75% पद स्थानीय निवासियों को दिए जाएंगे। इन पदों पर नियुक्ति के लिए राज्य सरकार द्वारा संचालित ट्रेनिंग प्रोग्राम को पूरा कर अब तक 2 लाख से ज्यादा युवा नौकरी पा चुके हैं।

▪ राज्य में औद्योगिक निवेश और रोजगार सृजन के लिए पांच औद्योगिक इकाइयों के साथ सरकार ने एमओयू हस्ताक्षर किए हैं। इससे लगभग 4000 करोड़ रुपए का निवेश राज्य में होगा तथा 6000 लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। वहीं राज्य के टेक्सटाइल उद्योगों में लगभग 10000 स्थानीय युवाओं को नौकरी दी जा रही है।

▪ बेहतर शिक्षा देने के लिए 80 सीएम स्कूल आफ एक्सीलेंस चल रहे हैं। जहां सीबीएसई पैटर्न पर अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई हो रही है। इसी शैक्षणिक सत्र से 325 प्रखंड स्तरीय लीडर स्कूलों का संचालन भी शुरू हो गया है। अगले 2 साल में 4041 पंचायत स्तरीय विद्यालयों को आदर्श विद्यालय के रूप में डेवलप किया जाएगा।

▪ स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए माध्यमिक विद्यालयों में 12809 टीजीटी और प्लस टू स्कूलों में 2509 पीजीटी शिक्षकों और 543 लैब असिस्टेंट की नियुक्ति की गई है। सहायक आचार्य के 26001 पद पर नियुक्ति प्रक्रिया जारी है।

▪ राज्य के विभिन्न विभागों में अनुबंध पर काम कर रहे लोगों कर्मियों के मानदेय में 50 से 100 फीसदी की वृद्धि की गई है।

▪ आदिवासी समाज के पारंपरिक प्रधानों और पदाधिकारी को मिलने वाली सम्मान राशि में भी 100 फीस अधिक की वृद्धि की गई है।

▪ 12वीं पास कर चुके वैसे छात्र जो पैसे के अभाव में हायर एजुकेशन नहीं ले पाते हैं उनके लिए गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत 15 लाख रुपए तक को लोन चार फीसदी साधारण ब्याज की दर पर उपलब्ध कराया जा रहा है।

▪ मरंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेसी छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत एसटी एससी ओबीसी और अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को सरकार अपने पैसे पर विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेज रही है।

▪ मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना इसी साल से शुरू किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत पीएचडी करने वाले वैसे छात्र जो नेट, गेट या जेट पास किए हैं उन्हें 22500 से 25000 रुपए प्रतिमाह फैलोशिप दिया जाएगा।

▪ बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत आने वाले लाभुकों को प्रतिवर्ष प्रति परिवार 15 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना से गुलाबी, पीला एवं हरा राशन कार्ड धारी 38 लाख परिवार लाभ उठा रहे हैं।

▪ मुख्यमंत्री अस्पताल संचालक एवं रखरखाव योजना भी शुरू की गई है। इस योजना के लिए एक अरब 35 करोड़ की राशि दी गई है। इस पैसे से अस्पताल भावनाओं के सुदृढ़ीकरण एवं आवश्यक जरूरत को पूरा किया जाएगा।

▪ झारखंड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के माध्यम से भी लोगों को लाभ दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 572 ग्रामीण रूट निर्धारित किए गए हैं उन रूप पर 92 बसों को परमिट दिया गया है। जो नि शुल्क लोगों को लाने ले जाने का काम कर रही है।

78 वें स्वतंत्रता दिवस के मंगलमय महापर्व का अभिनंदन

"आपके सुख दुःख का हमसफर"

कालीचरण सिंह

सांसद, चतरा संसदीय क्षेत्र

नालको में देशभक्ति के जोश के साथ मनाया गया 78वां स्वतंत्रता दिवस

सार्वजनिक क्षेत्र के 'नवरत्न' लोक उद्यम नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (नालको) ने राष्ट्र के साथ मिलकर 78वाँ स्वतंत्रता दिवस बड़े उत्साह और देशभक्ति के जोश के साथ मनाया। श्री श्रीधर पात्र, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने भुवनेश्वर में नालको के मुख्यालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और नालको परिवार को संबोधित किया। इस अवसर पर, श्री श्रीधर पात्र, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने नालको भवन के परिसर में पूर्व कर्मचारियों के लिए एक सुविधा केंद्र-सह-विश्राम कक्ष का भी उद्घाटन किया। समारोह में बड़ी संख्या में पूर्व कर्मचारियों ने भाग लिया और नालको के वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत की। इस अवसर पर कोटपाड़, कोरापुट के विख्यात पुरस्कार विजेता मंडली द्वारा शानदार ढ़ेमसा नृत्य प्रस्तुत किया गया। 78वां स्वतंत्रता दिवस नालको की अनुगुल और दामनजोड़ी स्थित परिचालन इकाइयों के साथ-साथ विशाखापत्तनम स्थित बंदरगाह सुविधा और देश के अलग-अलग व्याप्त क्षेत्रीय कार्यालयों में भी मनाया गया।

प्रथम तिमाही के नतीजे शुद्ध लाभ बढ़कर 601 करोड़ हुआ

भारत सरकार के खान मंत्रालय के तहत नवरत्न सीपीएसई और देश के अग्रणी एल्यूमिना और एल्यूमिनियम उत्पादक और निर्यातक नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (नालको) ने एक ठोस शुरुआत की है और वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में मजबूत परिचालन और वित्तीय प्रदर्शन दर्ज करते हुए असाधारण प्रदर्शन किया है। भुवनेश्वर में निदेशक मंडल की बैठक में दर्ज परिणामों के अनुसार, नाल्को ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 30 जून को समाप्त पहली तिमाही में प्रभावशाली परिणाम दर्ज किए हैं, जिसमें शुद्ध लाभ में 72% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में प्राप्त 349 करोड़ रुपये से बढ़कर 601 करोड़ रुपये हो गया, जबकि इस तिमाही के दौरान परिचालन से प्राप्त राजस्व 2856 करोड़ रुपये रहा। वित्त वर्ष 25 की पहली तिमाही के दौरान प्राप्त परिणाम विभिन्न कारकों जैसे कि लागत-कुशल संचालन, सकारात्मक घरेलू कारोबारी माहौल और अंतर्राष्ट्रीय धातु कीमतों में सुधार के कारण हैं। नाल्को के सीएमडी श्री श्रीधर पात्रा ने कहा कि नाल्को की पहली तिमाही का प्रदर्शन कंपनी की उत्कृष्टता और निरंतर विनिर्माण गति के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके अलावा, उत्कल डी कोल ब्लॉक से इन-हाउस कैप्टिव कोयले के प्रभावी संचालन ने बॉटम लाइन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

उल्लेखनीय है कि नाल्को ने पिछले कई वर्षों से एल्युमीनियम और एल्युमिना मूल्य श्रृंखला में मजबूत कारोबारी निष्पादन और बेहतर वित्तीय मापदण्ड दर्ज किए हैं। नाल्को ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 2 रुपये प्रति इक्विटी शेयर (5 रुपये अंकित मूल्य पर 40%) का अंतिम लाभांश भी घोषित किया है, जो 367.33 करोड़ रुपये होगा।

नई तकनीक और नए उपकरणों के उपयोग पर बल दिया

वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में 15 अगस्त, 2024 को उत्साह एवं उमंग के साथ "स्वतंत्रता दिवस" समारोह मनाया गया। अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक श्री जे. पी. द्विवेदी ने वेकोलि सुरक्षा गारद की परेड का निरीक्षण किया तथा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया। तत्पश्चात, उन्होंने टीम वेकोलि को संबोधित किया। उन्होंने अपने उद्बोधन में कंपनी के उत्पादन, उत्पादकता, पर्यावरण संरक्षण, खनन कार्यों में सुरक्षा, सीएसआर की गतिविधियों आदि के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कंपनी में नई तकनीक और नए उपकरणों के उपयोग पर बल दिया। उन्होंने उम्मीद जताई कि गत वर्ष की तरह, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड इस वित्तीय वर्ष में भी अपना उत्पादन का लक्ष्य पूर्ण करेगा। उन्होंने कर्मियों से आह्वान किया कि कोयला उत्पादन के माध्यम से देश की उन्नति में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।

सीएमडी श्री द्विवेदी के संबोधन के उपरान्त मुख्यालय प्रांगण में वृक्षारोपण किया गया। वेकोलि मुख्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में निदेशक तकनीकी (संचालन / योजना एवं परियोजना) श्री ए. के. सिंह, निदेशक (वित्त) श्री बिक्रम घोष, सीवीओ श्री अजय मधुकर म्हेत्रे, वेकोलि संचालन समिति के सदस्य, कल्याण मंडल के सदस्य, श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधि, मुख्यालय के महाप्रबंधक तथा विभागाध्यक्ष गण प्रमुखता से उपस्थित रहे।

तत्पश्चात, सीएमडी श्री जे. पी. द्विवेदी, निदेशक गण एवं अन्य गणमान्यों ने सांस्कृतिक भवन में आयोजित कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य के लिए कर्मियों तथा उनके बच्चों को दसवीं, बारहवीं एवं उच्च शिक्षा में उत्कृष्ट अंक लाने और विशिष्ट उपलब्धियाँ अर्जित करने के लिए सम्मानित किया। इस अवसर पर उल्लेखनीय कार्य करने के लिए खदानों एवं क्षेत्रों को भी सम्मानित किया गया। बेस्ट क्षेत्र के पुरस्कारों की श्रेणी में उमरेड क्षेत्र को प्रथम, वणी नॉर्थ क्षेत्र को द्वितीय तथा वणी क्षेत्र को तृतीय पुरस्कार से नवाजा गया।

कार्यक्रम में क्षेत्रीय महाप्रबंधक, विभागाध्यक्ष, अधिकारी एवं कर्मचारी गण बढ़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में कलाकारों द्वारा देश भक्ति के गीत प्रस्तुत किए गए।

देश के आदिवासियों को एक सूत्र में बांधने का काम किया जाएगाः सुखदेव भगत

दिल्ली में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सांसद सुखदेव भगत को सम्मानित किया गया. अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में आयोजित की गयी। इस बैठक में लोहरदगा लोकसभा के सांसद श्री सुखदेव भगत को आमंत्रित किया गया। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारियों के द्वारा सुखदेव भगत को बुके देकर एवं शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया।

मौके पर सुखदेव भगत ने कहा कि पूरे देश के आदिवासियों को एक सूत्र में बांधने के लिए आदिवासियों के मसीहा स्वर्गीय कार्तिक उरांव ने अखिल भारतीय विकास परिषद का गठन किया था। कार्तिक उरांव के विचारों को आत्मसात कर देश के आदिवासियों को एक सूत्र में बांधने का काम किया जाएगा।कांग्रेस पार्टी आदिवासियों के हित के लिए कृतसंकल्प है। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि आदिवासी इस देश के पहले मालिक है और पहले मलिक होने के कारण उन्हें

पूरा अधिकार मिलना चाहिए। सिर्फ जंगल जमीन का अधिकार नहीं वह तो मिलना चाहिए। शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार ,रोजगार का अधिकार, धन का अधिकार यह सब आदिवासियों को मिलनी चाहिए ।

श्री भगत ने कहा कि पेसा कानून, वन अधिकार कानून, जमीन का अधिकार कानून यह सब कांग्रेस पार्टी की देन है। आदिवासियों का मान सम्मान दिलाने उसकी प्राकृतिक आस्था, पूजा पद्धति और विशिष्ट रीति रिवाज के संरक्षण करने हेतु उनकी लड़ाई जारी रहेगा। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष सोमजी भाई दामोर, झारखंड प्रदेश आदिवासी विकास परिषद के अध्यक्ष गीताश्री उरांव सहित पूरे देश से कार्यकारिणी के सदस्य उपस्थित थे।

CCL
Fuelling Sustainable Growth

15 अगस्त, 2024

78वें स्वतंत्रता दिवस
की
हार्दिक शुभकामनाएँ

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

(भारत सरकार का एक उपक्रम/कोल इण्डिया लिमिटेड की एक अनुषंगी कम्पनी)

दरभंगा हाउस, रांची-834001 (झारखंड)

78 वें स्वतंत्रता दिवस की ढ़ेरों शुभकामनायें

15 august

टिंकू साहू

प्रोपराइटरः नवदा सर्विस, बिष्णुगढ़,
हिंदुस्तान पेट्रोलियम, जिलाः हजारीबाग

अदाणी फाउंडेशन की सराहना, स्वास्थ्य मंत्री ने प्रशस्ति पत्र प्रदान किया

अदाणी पावर झारखंड लिमिटेड के सीएसआर विंग अदाणी फाउंडेशन को झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने गोड्डा में टीबी मरीजों की बेहतर देखभाल के लिए सराहना करते हुए प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। यह कार्यक्रम रांची में आयोजित हुआ जहां अदाणी पावर झारखंड लिमिटेड के स्टेट कॉर्पोरेट अफेयर्स हेड संजीव शेखर और अदाणी फाउंडेशन के अधिकारी संतोष सिंह ने स्वास्थ्य मंत्री के हाथों प्रशस्ति पत्र प्राप्त किया।

गौरतलब है कि अदाणी पावर ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत गोड्डा के 353 टीबी मरीजों को गोद लिया था। सभी मरीजों को जिला प्रशासन के निर्देशानुसार नियमित पौष्टिक आहार पैकेट उपलब्ध कराया गया जिससे टीबी मरीजों की रिकवरी दर शानदार रही। अदाणी फाउंडेशन के कार्यों को सराहते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कार्य की सराहना की और उन्हें भविष्य में भी इसी प्रकार से समाज के कल्याण के लिए काम करने के लिए प्रोत्साहित किया।

इस अवसर पर अदाणी फाउंडेशन ने अपने सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत समुदाय के लिए निरंतर सहयोग का आश्वासन दिया।

विस्मिता तेज ने की सीसीएल की समीक्षा

सीसीएल मुख्यालय, राँची में अपर सचिव, कोयला मंत्रालय श्रीमती विस्मिता तेज ने सीसीएल के कोयला प्रेषण की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सीसीएल के सीएमडी श्री निलेन्दु कुमार सिंह, सीआईएल के निदेशक (मार्केटिंग) श्री मुकेश चौधरी, निदेशक (वित्त) श्री पवन कुमार मिश्रा, निदेशक (कार्मिक) श्री हर्ष नाथ मिश्र, निदेशक (तकनिकी/संचालन) श्री हरीश दुहान, रेलवे के सीनियर डीओएम, राँची डिवीज़न श्रीमती श्रेया सिंह, सीनियर डीओएम, धनबाद डिवीज़न श्री अंजय तिवारी एवं सीसीएल के अधिकारीगण मौजूद थे। इस बैठक में कोयले की निर्बाध आपूर्ति को सुनिश्चित करने से सम्बंधित कई महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गयी। कोयला प्रेषण बढ़ाने तथा उपभोक्ता संतुष्टि सुनिश्चित करने से संबंधित मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। ज्ञात हो कि सीसीएल देश की ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति हेतु कृतसंकल्पित है। इसलिए सभी उपभोक्ताओं को समय पर पर्याप्त कोयले का प्रेषण सीसीएल की प्राथमिकता है। उक्त बैठक के पश्चात् श्रीमती तेज ने कोयला उपभोक्ताओं के साथ एक अन्य बैठक में बातचीत की।

एनटीपीसी स्वयंसिद्धा लेडीज क्लब के सदस्यों द्वारा वृक्षारोपण

वृक्षारोपण या पेड़ लगाने का कार्य पर्यावरण की देखभाल का एक महत्वपूर्ण पहलू है क्योंकि यह पर्यावरण संरक्षण की दिशा में विभिन्न तरीकों से मदद करता है जैसे कि जैव विविधता, मिट्टी संरक्षण, जल संरक्षण और जलवायु को बनाए रखना, जैसा कि कहा जाता है "वह जो पेड़ लगाता है, एक आशा का पौधा लगाएं"। वृक्षारोपण और चल रहे मानसून के लाभों को ध्यान में रखते हुए, एनटीपीसी स्वयंसिद्धा लेडीज क्लब, कोयला खनन मुख्यालय, रांची ने नीम, पीपल और बरगद के पेड़ जैसे पेड़ लगाए, जो त्रिवेणी वृक्ष के रूप में लोकप्रिय हैं, वृक्षारोपण अभियान था श्रीमती रेखा जैन, अध्यक्ष, स्वयंसिद्धा लेडीज क्लब, कि मार्गदर्शन में किया गया ।

डुंगरी गांव, रांची में त्रिवेणी वृक्षों का वृक्षारोपण किया गया। यह नेक कार्य ग्राम पंचायत प्रधान और आशा होम, रांची के सदस्यों की मदद से संभव हुआ। इस अवसर पर, ग्राम प्रधान ने वृक्षारोपण के लिए सभी महिला क्लब सदस्यों को धन्यवाद दिया। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक छोटा सा कदम है ।

एक अन्य पहल में, स्वयंसिद्धा लेडीज क्लब और आशा होम के सहयोग से एनटीपीसी सीएसआर के तहत सफल कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद प्रशिक्षुओं को सिलाई और सिलाई कक्षाओं के दूसरे बैच में समापन प्रमाण पत्र प्रदान किया गया।

इस अवसर पर अध्यक्ष श्रीमती रेखा जैन ने

प्रमाण पत्र वितरण की पहल की और प्रशिक्षुओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित किया जिसके बाद उपाध्यक्ष श्रीमती शिखा रस्तोगी और उपाध्यक्ष ,श्रीमती पूर्णिमा श्रीखंडे, महासचिव श्रीमती दीपा, संयुक्त सचिव श्रीमती परमेश्वरी, सांस्कृतिक सचिव, श्रीमती अनिता प्रसाद, श्रीमती मनसा वर्मा, कल्याण सचिव। इस अवसर पर कोषाध्यक्ष श्रीमती स्निग्धा माझी और अन्य सदस्य उपस्थित थे।

एन सी एल
NCL

Fueling Possibilities Fueling Nation

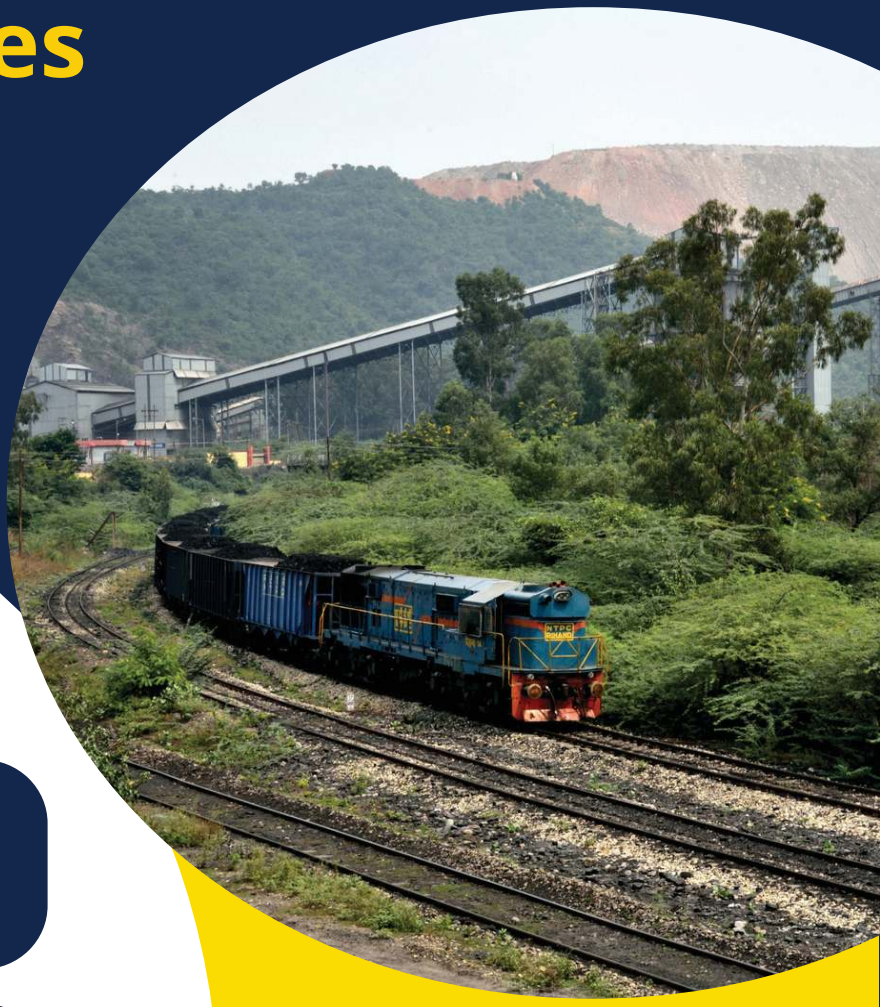

MILESTONES

Coal Production
136.15 MT

Coal Despatch
137.63 MT

OBR 513.56
MCuM

Northern Coalfields Limited
A Miniratna Company
(A Subsidiary of Coal India LImited)
Singrauli (M.P.) 486889

/northerncoalfields
@NCL_SINGRAULI
ncl_singrauli
/northerncoalfields
/northerncoalfields
/northerncoalfields
/www.ncl.cil.in

छोटानागपुर स्वतंत्रता संघर्ष सेनानियों में सबसे पहले फांसी पाने वालों में **ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव**

▪ ब्रजभूषण पाठक

अब फिर से आया है आजादी दिवस। 15 अगस्त। जश्न का दिन। लेकिन यह दिन जश्न से ज्यादा जिम्मेदारियों के दिन सा लगता है। जिन शहीदों के दम पर हमारा देश आजाद हुआ आज उनके वंशजों को भी याद करने का दिन होना चाहिए और इस 15 अगस्त को उन सभी अनाम आत्माओं को नमन करने का भी दिन होना चाहिए जिनकी कुर्बानियों की गाथा गाना असंभव है क्योंकि वो हर व्यक्ति जिसने ब्रितानी हुकूमत की गोलियां और लाठियां खाकर अपने प्राणों की आहुति दी शहीद हैं और उससे कम नहीं।

हमारे राज्य झारखंड के लिए अगस्त महीने का महत्व और भी गहरा जाता है जब हम शहीद शिरोमणि ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव का जन्म दिवस मनाते हैं जिन्हें ब्रिटिश हुकूमत ने 16 अप्रैल 1858 में सरेआम फांसी की सजा दी।

अमर शहीद ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव का जन्म 12 अगस्त 1817 को वर्तमान रांची जिला के सतरंजी गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम ठाकुर रघुनाथ शाहदेव व माता का नाम चागेश्वरी कुंवर था। ठाकुर विश्वनाथ, नागवंशी क्षत्रिय फणि मुकुट राय के वंशज थे। ज्ञातव्य हो कि फनी मुकुट राय, मदरा मुंडा के पोस पुत्र थे और मदरा मुंडा ने अपना राज्य फणि मुकुट राय को सौंप दिया था। इस प्रकार झारखंड में नागवंशियों का राज्य प्रारंभ हुआ।

ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव की धर्मपत्नी का नाम बागेश्वरी कुंवर था और उनके एक संतान थे जिनका नाम ठाकुर कपिल नाथ शाहदेव था। ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव बचपन से ही आजादी पसंद व्यक्तित्व के मालिक थे और राजनीति पर अपनी पकड़ रखते थे। उनका बचपन अपने माता-पिता की छाया में बड़ी ही सुख पूर्वक व्यतीत हुआ। नागवंशी शासकों की एक विशेषता रही थी कि ये सभी अत्यंत धार्मिक और प्रजापालक होते थे।

अंग्रेजों और मुगलों के शासन के पूर्व यहां की राज्य प्रणाली में कराधान जैसी कोई व्यवस्था नहीं होती थी और ना ही शासन प्रणाली की कोई क्लिष्ट व्यवस्था थी। पर्वतों और जंगलों से घिरे इस क्षेत्र में बाहरी राजनीतिक उठा पटक का प्रभाव नगण्य होता था और शासन व्यवस्था परंपरागत रूप से चलती थी। परंतु मुगलों और अंग्रेजों के आगमन से यहां की राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव के चिन्ह दृष्टिगोचर होने लगे।

ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव ने बड़कागढ़ राज्य की जिम्मेवारी 1840 ईस्वी में संभाली। राज्य का

उत्तरदायित्व आते ही उन्होंने अपना काम प्रारंभ किया। ठाकुर साहब 94 गांव की व्यवस्था, प्रबंधन करते थे। अंग्रेजो के शासनकाल में उस समय भी धर्मांतरण का कार्य होता था, चूंकि शासन उन्हीं का था उन्हें पर्याप्त सुविधाएं मिल जाती थी। जिनकी नजर सदा दूसरों की संपदा पर होती थी और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आक्रमण से वे देशी रियासतों को कमजोर करने का कोई तरीका नहीं छोड़ते थे।

छोटा नागपुर धर्म परिवर्तन की समस्या से भी आक्रांत था और ठाकुर विश्वनाथ के प्रयासों से इस कार्य से भी अंग्रेजों को परेशानी झेलनी पड़ती थी। अंग्रेजों ने कूटनीतिक चालें चलनी शुरू की। भारत में किसी भी राज्य में अंग्रेजों की हुक्म उदूली नहीं होती थी सिवाय बड़का गढ़ के। अंग्रेजों ने ठाकुर विश्वनाथ के खिलाफ एक अघोषित युद्ध छेड़ रखा था। उनकी जमीनों पर कब्जा का प्रयास करवाया जाने लगा और सुदूर गांवों में उनके दुष्प्रचार का कार्य होने लगा। ठाकुर विश्वनाथ ने जब हुक्मरानों से इसकी आपत्ति दर्ज की तो अंग्रेजों ने चुप्पी साध ली।

अब ठाकुर विश्वनाथ को लगने लगा कि अंग्रेज बस उन्हें एक जमींदार मात्र समझते हैं और राजा तो वे नाम मात्र के हैं। अंग्रेजों को तो सिर्फ मालगुजारी चाहिए थी जनता से सीधा संबंध तो ठाकुर विश्वनाथ का था, उन्होंने अब कुछ नया करने की योजना पर काम करना प्रारंभ किया।

सतरंजी से अपनी राजधानी हटिया बनाई यह स्थान श्री जगन्नाथ स्वामी जी के मंदिर के निकट ही है और यहां से उन्होंने अपनी संगठनात्मक क्षमता का उपयोग करते हुए अपनी सेना बनानी शुरू की और आसपास के महत्वपूर्ण पीड़ित जमींदारों को जो उनके ही पूर्ववर्ती राजाओं के द्वारा स्थापित थे उन सभी को अंग्रेजों की दमनात्मक व कूटनीतिक चालों से परिचय करवाया और एक नई क्रांति की इबारत चलाने, बनाने की ठान ली। अब अंग्रेजों से रहम नहीं युद्ध की भाषा में ही बात करनी होगी। सन 1855 में उन्होंने अपने राज्य को स्वतंत्र घोषित कर दिया। ऐसी स्थिति अंग्रेजों के लिए अकल्पनीय थी। ठाकुर विश्वनाथ के साथ जनता और जमींदारों का समर्थन था। छोटानागपुर के अनेकों स्वतंत्रता प्रेमियों ने ठाकुर साहब की सशस्त्र क्रांति में सहयोग देने की ठान ली। ठाकुर विश्वनाथ ने कसम ही खा ली थी, "जिएंगे तो आजाद होकर" और उनके सेनानी, सहयोगों सहयोगियों की भी यही राय थी। इस संबंध में एक बात का उल्लेख करना अत्यंत ही समीचीन होगा। ठाकुर विश्वनाथ को छोटानागपुर स्वतंत्रता संघर्ष की सेनानियों में सबसे पहले फांसी दी गई थी। जब ठाकुर ठाकुर विश्वनाथ की फांसी का वक्त आया उस समय उनके अनन्यतम सहयोगी पांडेय गणपत राय भी उनके साथ थे। पांडेय गणपत राय ने भी ठाकुर विश्वनाथ के सशस्त्र आंदोलन में अपना सब कुछ पीछे छोड़कर जान की बाजी लगा दी थी।

लोहरदगा से रांची, पलामू तक झारखंडी विद्रोह को सुलगाने में उन्होंने ठाकुर साहब के दाहिने हाथ का काम किया था और अंत तक एक सच्चे क्रांतिकारी की भूमिका निभाते हुए उन्होंने ठाकुर विश्वनाथ की फांसी से पहले यह महावाक्य कहा था, "डरू मईत ठाकुर,

लाल विनोद नाथ शाहदेव

चढ़ू फांसी, दू चाईर दिन में हमहों आवत ही।" वर्तमान में भौरों स्थित गांव जिला लोहरदगा के निवासी थे पांडेय गणपत राय।

ठाकुर साहब के सशस्त्र क्रांति के निर्णय ने पूरे पठारी प्रदेश में आजादी की लहर फैला दी। उधर पोड़ाहाट के राजा अर्जुन सिंह ने क्रांति का जिम्मा लिया और अपनी तलवार की धार से अंग्रेजों को खूब मजा चखाया।

अंग्रेज हतप्रभ थे। किंकर्तव्यविमूढ़। बड़कगढ़ पर रामगढ़ बटालियन की डोरंडा छावनी के सिपाहियों का आक्रमण हुआ। कुछ ही अंग्रेज सिपाही जान बचाकर भाग पाए।

बड़का गढ़ भारतवर्ष का पहला स्वतंत्र राज्य बन गया। अब यहां देशी हुकूमत कायम हो गई। अंग्रेज हैरान परेशान। अंग्रेजी फौज को अपने ऊपर भरोसा नहीं रहा। यहां के तत्कालीन कमिश्नर से कोलकाता से फौजी दस्ता भेजने का अनुरोध किया। वहां की वहां के अधिकारी ने जवाब में लिखा, " वहां तो फौज है ही, यहां भी फौज की कमी है, जो है उनका इस्तेमाल किया जाए,"

यहां के अधिकारी ने लिखा, "यहां जितनी फौज है उसके लिए तो ठाकुर विश्वनाथ अकेला ही काफी है।" (श्री विनोद नाथ शाहदेव, वंशज बड़का गढ़ रियासत के द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर) ठाकुर विश्वनाथ के तलवार उठाने का प्रभाव बहुत ही व्यापक था। उन्होंने आजादी की चाह जमींदारों, समाज के नायकों और जन-जन के मन में जगा दी यही कारण रहा कि अंग्रेजों की किलिंग लिस्ट में इनका नाम सबसे ऊपर था।

आदिवासियों ने भी इस आंदोलन में नागवंशी राजाओं को पूर्ण सहयोग दिया। 1857 का विद्रोह झारखंड क्षेत्र में पूर्ण रूपेण सुलग चुका था। रांची के बड़का गढ़ से उठी आवाज़ देवघर, हजारीबाग, चतरा, चुटुपालु में फैल गया। ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव, पांडेय गणपत राय, रामगढ़ बटालियन के जमादार माधो सिंह, डोरंडा बटालियन के जय मंगल पांडेय, विश्रामपुर के चेरो सरदार भवानी राय, टिकैत उमराव सिंह, पलामू के नीलांबर और पीतांबर, शेख भिखारी, नखलौट मांझी, ब्रजभूषण सिंह आदि के नेतृत्व में जोरदार बगावत हुई।

ठाकुर विश्वनाथ से लोहा लेना अंग्रेजों को महंगा पड़ा। इस पठारी व जंगलों से आच्छादित प्रदेश में आजादी की इस दीवानगी ने अंग्रेजों को हैरान कर दिया। कोने-कोने से विद्रोहियों की उठने वाली आवाजों ने अंग्रेजों को भयभीत कर दिया और ठाकुर विश्वनाथ को पकड़ने के लिए उन्होंने सघन अभियान चलाया। उनकी संगठनात्मक शक्ति का कमाल था कि उनके शंखनाद से गोनो पिंगुआ, बारू मानकी, खरी तांती, टिबरू संथाल, रूपा मांझी, रामबनी माझी, अर्जुन मांझी, कोका कुमार जैसे आदिवासी नायकों ने अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र आंदोलन कर दिया। सम्मुख संघर्ष में अंग्रेज ठाकुर विश्वनाथ को कभी भी नहीं हरा पाए। बड़का गढ़ पर 1855 का आक्रमण बेकार हो गया था, अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी थी।

1855 में उठी आवाज़ से अंग्रेज 1857 तक खामोश ही रहे। 1857 में जब जगत प्रसिद्ध आजादी का सशस्त्र विद्रोह पूरे भारत में फैला तो ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव जो पहले से ही संघर्षरत थे इस आंदोलन की अगुवाई करने लगे। हर मोर्चे पर अंग्रेजों को मात देते हुए जब यह वीर पुरुष अपने ही जागीरदार पिठौरिया परगैनत जगतपाल सिंह के घर पर आराम कर रहे थे, जगतपाल सिंह की गद्दारी का शिकार हो गए। इस जागीरदार ने आराम करते हुए ठाकुर विश्वनाथ के कमरे की कुंडी चढ़ा दी और अंग्रेजों को खबर कर दी। वे पकड़ लिए गए, अंग्रेजों को आखिरकार एक अहसान फरामोश आदमी यहां भी मिल ही गया था। मुकदमा चला। ठाकुर विश्वनाथ को फांसी की सजा मिली।

यहां एक रोमांचक सत्य का उल्लेख करना समीचीन होगा। ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव के खिलाफ उनके ही जागीरदार परगैनत जगतपाल सिंह का बयान उनकी फांसी का आधार बना। उसके इस अप्रत्याशित व्यवहार से ठाकुर साहब की आत्मा दुखी हुई और उन्होंने उसे श्राप दिया, "तोंय निरवंश होय जाबे, आउर तोर घर में बजर गिरी, तोंय बरबाद होय जाबे!" ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव को फांसी देखकर अंग्रेजों ने चैन की सांस ली। जागीरदार परगैनत जगतपाल सिंह सचमुच में निरवंश हो गए, उनके घर अभी भी पिठौरिया में जमींदोज अवस्था में देखा जा सकता है, इतना ही नहीं उनके उनके वंश का अंत हो गया इस प्रकार ठाकुर विश्वनाथ के श्राप ने अपना प्रभाव दिखाया।

इधर ठाकुर विश्वनाथ के वंशजों पर भी मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। अंग्रेजों ने ठाकुर साहब की संपूर्ण संपत्ति को जब्त कर लिया और उनके निवास को तोड़फोड़ कर गिरा दिया। ठाकुर साहब की धर्मपत्नी बाणेश्वरी कुंवर अपने नाबालिग बच्चे ठाकुर कपिल नाथ शाहदेव को लेकर वर्तमान के गुमला जिला स्थित खोरा गांव में 14 वर्षों तक निर्वासित जीवन व्यतीत करती रही। उपयुक्त समय पाकर उन्होंने अपने को अपने पुत्र सहित उपस्थित किया और अपने राज्य को अंग्रेजों से वापस लेने की बात की। अंग्रेजों ने उन्हें जीविका निर्वाह के लिए 30 मात्र की मासिक राशि देने की कृपा की और 500 देकर उन्हें जगन्नाथपुर परिसर में अपना घर बनाने देने की कृपा की।

ठाकुर विश्वनाथ के वंशज आज भी यहीं निवास कर रहे हैं और वर्तमान में अपनी अचल संपत्ति को प्राप्त करने के लिए न्यायिक प्रक्रिया में उलझे हुए हैं। आशा है इस महान स्वतंत्रता सेनानी के वंशजों को पूर्ण सम्मान व न्यायालय से पूर्ण न्याय की प्राप्ति होगी।

मात्र कुछ ही अपनी उत्कृष्टता की छाप छोड़ सकते हैं

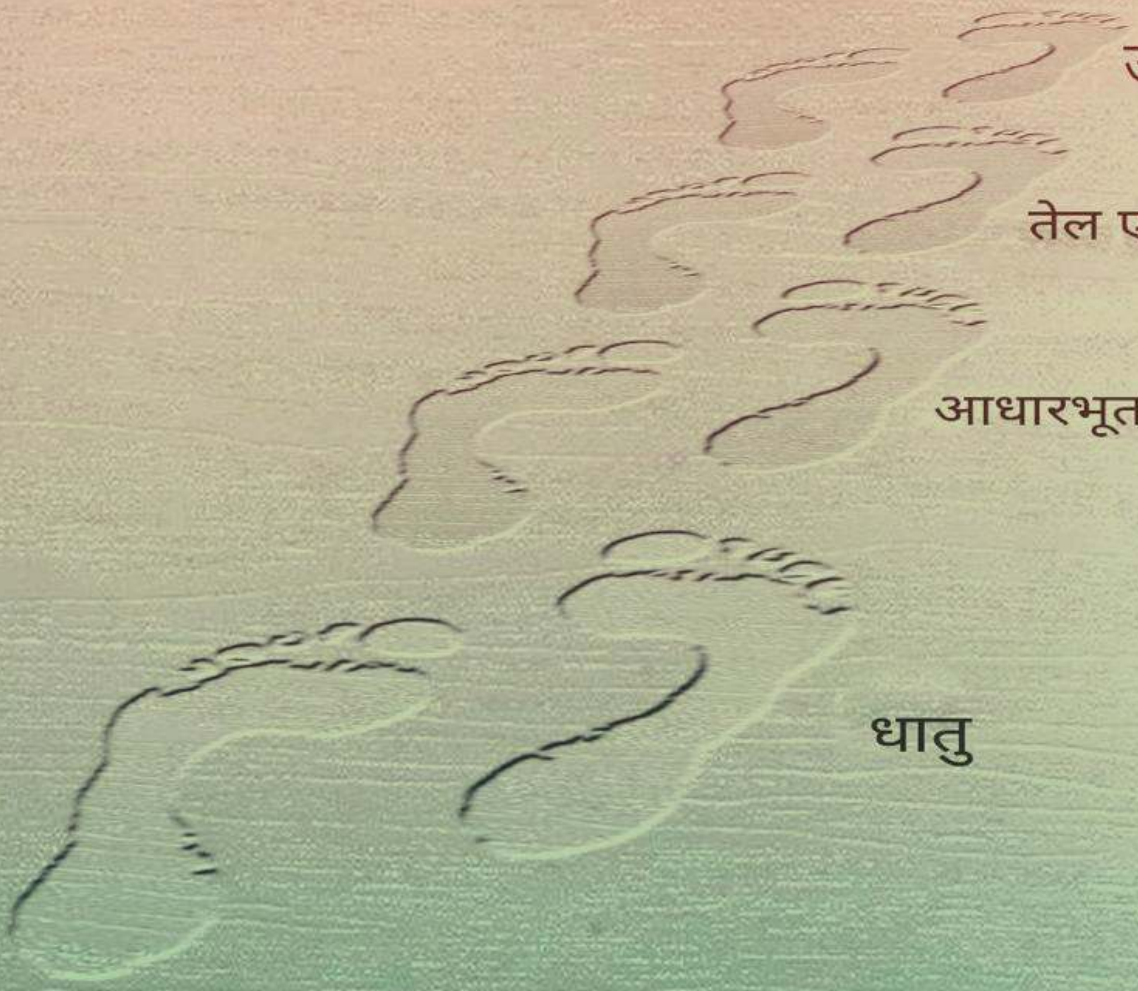

विगत 6 दशकों से भी अधिक समय से, मेकॉन ने धातु, आधारभूतसंरचना,
तेल एवं गैस तथा ऊर्जा के क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ी है

अभियांत्रिकी उत्कृष्टता का केन्द्र
.....अपेक्षा से अधिक पर लक्ष्य

आत्मनिर्भर भारत

मेकॉन लिमिटेड
(भारत सरकार का संस्थान)
MECON Limited
(A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE)

ओलंपिक में अधूरी रह गयी आस लेकिन पैदा हुआ जबरदस्त आत्मविश्वास

▪ चंचल भट्टाचार्य

भारतीय खेल के संदर्भ में यदि बात की जाये तो पेरिस में आयोजित 33 वें ओलंपिक ने एक बार फिर से प्रमाणित कर दिया है कि भारतीय खेल और भारतीय खिलाड़ियों के कदम धीरे-धीरे ही सही लेकिन निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और अब भारतीय कदमों के थमने का सवाल ही नहीं उठता.

26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक पेरिस में खेले गये ओलंपिक की आधिकारिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यही रही कि भारत के कुल 117 एथलीटों ने फ्रांस के पेरिस की मेजबानी और 16 अतिरिक्त शहरों में समाहित कार्यक्रम (जिसमें मार्सिले में नौकायन एवं ताहिती में सर्फिंग के लिये शामिल स्थान शामिल है) में एक रजत पदक के साथ पाँच कास्य पदक जीते और वह पदक तालिका में 71 वें स्थान पर रहा. लेकिन वास्तव में व्यावहारिक रूप में उपलब्धियाँ इससे कहीं अधिक बढ़कर है.

मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में भारत के लिये महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में पहला पदक जीता और ओलंपिक शूटिंग पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनीं. इसके बाद उन्होंने सरबजोत सिंह के साथ मिश्रित टीम 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीतकर किसी एक ओलंपिक आयोजन में दो पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनकर इतिहास में अपना नाम लिख दिया.

स्वप्निल कुसाले ने पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन निशानेबाजी में तीसरा पदक जीतकर किसी एक ओलंपिक खेल में किसी एक ही खेल में भारत के लिये अबतक सबसे अधिक पदक जीतने वाला बना दिया.

भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस में कांस्य पदक के साथ अपनी टोक्यो 2020 की सफलता को बरकरार रखा. जबकि भाला फेंक में रजत पदक जीतने के बाद नीरज चोपड़ा सबसे सफल व्यक्तिगत ओलंपियन बन गये लेकिन टोक्यो 2020 की उनकी चमक फीकी पड़ गयी जब उन्होंने भारत का एकमात्र स्वर्ण पदक जीता था.

पेरिस में अमन सेहरावत भारत के सबसे युवा ओलंपिक पदक विजेता भी बने जब उन्होंने पुरुष फ्रीस्टाइल 57 किग्रा भारवर्ग कुश्ती में कांस्य पदक जीता. यह तो रही अपनी उपलब्धियाँ और इसपर हमें ख़ुश हो जाना चाहिये. लाज़िमी है यह वैसे एक दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो अपना भारत, पेरिस 2024 ओलंपिक से खुशियों से ज़्यादा दर्द लेकर आया. भारत छह वैसे संभावित पदकों से चूक गया जहाँ अधिकतर में मामूली अंतर से भारतीय एथलीट अपने-अपने इवेंट में चौथे स्थान पर रहे. इसमें लक्ष्य सेन , मीराबाई चानू और मनु भाकर शामिल हैं. इनमें मनु भाकर आसानी से अपना तीसरा कास्य पदक जीत सकती थी लेकिन उफ...

खेल खेल होता है और स्पर्धा भी स्पर्धा ही होती है.

उधर ऐतिहासिक फाइनल से पहले विनेश फोगाट को निर्धारित 50 किलोग्राम वर्ग में फाइनल के दिन क़रीब 100 ग्राम अधिक वज़न के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया. यहाँ भी नियम, नियम होता है और सभी के लिये बराबर पर इस नियम के कारण करोड़ो की स्वर्ण की आस टूट गयी अन्यथा टोक्यो की तरह एक गोल्ड अपने हिस्से में अबकी बार भी हो सकता था.

पेरिस ओलंपिक 2024 में 16 स्पर्धाओं तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, मुक्केबाजी, घुड़सवारी, गोल्फ, हॉकी, जूडो, नौकायन, निशानेबाजी, तैराकी, टेबल टेनिस और टेनिस में भारतीय खिलाड़ियों ने भाग लिया और पदकों के लिहाज़ से प्रदर्शन सामने है.

इस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा, बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु, भारोत्तोलक मीराबाई चानू, मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन और हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली भारतीय पुरुष हॉकी टीम के चुनिंदा सदस्य पेरिस 2024 के पहले के ओलंपिक खेलों में भारतीय दल के सदस्य के रूप में पदक विजेता रह चुके हैं लेकिन इनमें से अनेक अबकी बार चूक गये.

कुल मिलाकर भारत ने अबतक ओलंपिक में कुल 41 पदक जीते हैं. दिलचस्प और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि पेरिस 1900 में नॉर्मन प्रिचर्ड के दोहरे रजत पदक से भारत का खाता खुला था जबकि अबकी बार मनु भाकर ने दोहरा कास्य जीतकर नॉर्मन प्रिचर्ड के

कीर्तिमान की याद दिला दी.

केडी जाधव ने हेलसिंकी 1952 में कुश्ती में कांस्य पदक जीतकर, ओलंपिक पदक विजेताओं की सूची में शामिल होने वाले पहले व्यक्तिगत एथलीट बने थे. उधर भारोत्तोलक में कर्णम मल्लेश्वरी सिडनी 2000 में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला बनीं थीं. राइफल निशानेबाज अभिनव बिंद्रा बीजिंग 2008 में व्यक्तिगत स्पर्धा में ओलंपिक स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय थे और टोक्यो 2020 में नीरज की भाला फेंक जीत से पहले एक दशक से अधिक समय तक ऐसा करने

वाले एकमात्र खिलाड़ी थे.

इतिहास की बातें एक बार फिर. पुरुष हॉकी ने आठ स्वर्ण सहित 13 पदकों के साथ भारत की ओलंपिक पदक तालिका में सबसे बड़ा योगदान दिया है. जबकि कुश्ती, आठ पदकों के साथ दूसरे स्थान पर है. टोक्यो 2020 में भारत, एक स्वर्ण सहित सात पदक जीतकर अपने अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ अब भी बरकरार रहा क्योंकि अबकी बार पेरिस में टोक्यो के रिकॉर्ड को तोड़ने का सपना ही टूट गया.

पेरिस में विविध खेलों स्पर्धाओं के आधार पर बात की जाये तो भाला फेंक में एक रजत, हॉकी में एक कास्य, शूटिंग में तीन कास्य, कुश्ती में एक कास्य और कुल मिलाकर चार खेलों में एक रजत, पाँच कास्य सहित छह पदक अपने हिस्से आये.

सभी भाग लेनेवाले के दृष्टिकोण से अमेरिका 40 स्वर्ण रजत 42 कास्य और कुल मिलाकर 126 पदकों के साथ पहले स्थान पर रहा चीन क्रमशः 40, 27,24 और कुल साथ पहले स्थान पर रहा. चीन क्रमशः 40,27,24 और कुल 91 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा. तीसरे स्थान पर रहा जबकि ऑस्ट्रेलिया चतुर्थ, मेजबान फ्रांस पांचवें और अपना भारत 71 वें स्थान पर रहा.

पेरिस ओलंपिक में बहुत सारी उपलब्धियाँ ऐसी रही जो भविष्य के लिये भरोसा जागती है. शूटिंग में पहली बार पदक जीतनेवाली भारतीय महिला किसी एक ओलंपिक में दो पदक जीतनेवाली भारत की पहली महिला एथलीट बनीं लेकिन शूटिंग में भारत के लिये तीसरा मेडल जीतने से वे चूक गयीं. टेबल टेनिस में भारत की ओर से अभी तक का श्रेष्ठ प्रदर्शन रहा. मनिका एवं श्रीजा प्री-क्वार्टर फाइनल में पहुँचे.

ओलंपिक में पहली बार तीरंदाजी में भारत ने मेडल इवेंट में अपनी चुनौती प्रस्तुत की. इसके अलावा भारत के परंपरागत और सबसे महत्वपूर्ण खेल हॉकी में उसने 52 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया को हराया. ओलंपिक हॉकी में टोक्यो में भी भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था और इस बार भी यह बरकरार रहा. 1968-72 के बाद भारत में लगातार दो ओलंपिक खेलों में हॉकी में मेडल जीता है और यह भी अपने-आप में एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ते भारतीय हॉकी का प्रमाण है. भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन सेमीफाइनल में पहुँचने वाले पहले पुरुष शटलर बनें. भारत ने कुश्ती में 2008 से चला आ रहा अपना वह कीर्तिमान भी बरकरार रखा जब भारत लगातार ओलंपिक मेडल जीतता रहा है. इस साल यह रिकॉर्ड अमन सेहरावत ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर बरकरार रखा.

भारत की ओर से कुश्ती में छह पहलवानों ने अपनी चुनौती पेश की जिसमें पाँच महिला पहलवानों के साथ ही एक पुरुष पहलवान अमन सेहरावत थे जिन्होंने 57 किलो ग्राम भारवर्ग में भारत को जीत दिलायी. भारत के हाथ से पेरिस में छह पदक फिसल गये. कुल मिलाकर एक पहलु से देखा जाये तो पेरिस में भारतीय एथलीटो का प्रदर्शन टोक्यो से बेहतर रहा है. 6 मौके ऐसे आये जब भारत कांस्य पदक जीत सकता था. इसमें सबसे महत्वपूर्ण पेरिस में दो पदक जीतने वाली निशानेबाज मनु भाकर रहीं जो चौथे स्थान पर आने के कारण अपने तीसरे पदक से चूक गयी. अर्जुन बबूता और नरूका-माहेश्वरी की जोड़ी भी निशानेबाजी की अपनी अपनी स्पर्धाओं में छोटे-से अंतर से कांस्य पदक चूक गयीं. बैडमिंटन में लक्ष्य सेन ने कांस्य पदक के मुकाबले में पहला गेम जीतकर अच्छी शुरुआत की थी लेकिन लगातार दो गेम हार कर वे बाहर आ गये और फिर वही हुआ जो ऐसे मौके पर होता है. उम्मीदें चकनाचूर हो गयी. पिछले ओलंपिक में पदक विजेता मीराबाई

चानू भी इतिहास रचने के करीब पहुँचकर विफल रही. इस बार भारत को तीरंदाजों से बहुत आशा थी लेकिन एक बार फिर से उन्होंने निराश किया और सफलता और पदक की दहलीज तक पहुँचकर भी धीरज और अंकित की जोड़ी के हाथ असफलता लगी. लेकिन कुल मिलाकर जिस घटना ने पेरिस ओलंपिक के साथ ही भारतीय खेल जगत में सुर्खी बटोरी वह थी भारत की पहलवान विनेश फोगाट का 50 किलोग्राम भारवर्ग रेसलिंग फाइनल में पहुँचकर भी चूक जाना.

दरअसल जैसे ही फोगाट ने सेमीफाइनल में विजय प्राप्त की उसके बाद गोल्ड या सिल्वर पक्का था. लेकिन ऐन मुकाबले के दिन विनेश फोगाट का वजन निर्धारित 50 किलोग्राम से 100 ग्राम अधिक पाया गया और उन्हें फाइनल खेलने के अयोग्य करार दिया गया. बाद में काफी जद्दोजहद के बाद भी फोगाट के रजत पदक के दावे के ख़ारिज कर दिया गया. यही है पेरिस के 33 वें ओलंपिक की वह कहानी जो भारतीय दृष्टिकोण के मद्देनज़र इतिहास में दर्ज़ है. यहाँ ख़ुशी है, दर्द है और साफ-साफ यह भी नज़र आ रहा है कि क्या एवं कैसा मर्ज़ है?

Ministry of Ports, Shipping & Waterways
Government of India

VISAKHAPATNAM PORT AUTHORITY

ITUWTSA EXPO2024

- The only Port with Deepest Container Terminal
- State of the Art Technology & Mechanization
- World Class International Cruise Terminal
- Complete transactions through online Digital Platform
- ISPS compliant with CCTV surveillance
- 2nd Gateway Port to Nepal EXIM cargo
- Tailor made service to suit user's requirement.
- Highest Exporter of Sea Food in India in 2023-24
- Green Port operating completely on Solar Power (10 MW Solar Power Plant)
- Port with specialised facilities for handling Multi Commodities - Coal, Ore, Coke Petroleum, Chemicals, Containers , Fertilizers, Food Grains and General cargo
- End to End mechanised facility for Coal, Iron ore, Alumina, Manganese Ore and Liquid Cargo.
- Engine on Load facility (EOL) for Coal that can load a rake in an hour
- Covered Storage sheds in Port area of 40468 Sq.Mtrs to store 3.5 MTPA

The Only Indian Major Port entered in 20th Position Globally and 19th position in CPPI 2023 by World Bank

SAGARMALA
PORT-LED PROSPERITY

CLEANEST MAJOR PORT IN INDIA

e-reg.vpt@gov.in
www.vizagport.com
Port Area, Visakhapatnam - 530035
+91-891- 2873120

90 YEARS

कंगना रनौत की नयी फिल्म इमरजेंसी पर विवाद

हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से BJP सांसद, एक्ट्रेस कंगना रनौत अपकमिंग मूवी इमरजेंसी विवादों से घिर गई हैं। कंगना की ये फिल्म पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में लगाई गई इमरजेंसी पर बनाई गई है। फिल्म 6 सितंबर को रिलीज होगी।

इससे पहले पंजाब के निर्दलीय सांसद सर्बजीत सिंह खालसा ने ट्रेलर में दिखाए गए दृश्यों पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि इसमें सिखों को गलत तरीके से पेश किया गया है। उन्होंने केंद्र सरकार को लेटर लिखकर फिल्म की रिलीज रोकने की मांग की है। सर्बजीत सिंह खालसा ने कहा, 'नई फिल्म 'इमरजेंसी' में सिखों को गलत तरीके से पेश करने की खबरें सामने आ रही हैं, जिससे समाज में शांति और कानून की स्थिति बिगड़ने की आशंका है। अगर इस फिल्म में सिखों को अलगाववादी या आतंकवादी के रूप में दिखाया गया है तो यह एक गहरी साजिश है। यह फिल्म एक मनोवैज्ञानिक हमला है, जिस पर सरकार को पहले से ध्यान देकर दूसरे देशों में सिखों के प्रति नफरत भड़काना बंद कर देना चाहिए।' सरबजीत सिंह खालसा बेअंत सिंह के बेटे हैं। बेअंत सिंह पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या में शामिल था।

Yuvraj की जिंदगी पर बायोपिक का ऐलान

इंडियन क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज युवराज सिंह पर अब फिल्म बनने जा रही है। इस बात की जानकारी फिल्म एनालिस्ट तरण आदर्श ने अपने एक पोस्ट के माध्यम से दी है। इस खबर के सामने आते ही युवराज के चाहने वाले खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। जैसे ही ये खबर सामने आई तो लोगों के दिमाग में एक और प्रश्न आया कि बायोपिक में युवराज सिंह का रोल कौन सा एक्टर निभाएगा। युवी वही शानदार खिलाड़ी हैं जिन्होंने साल 2007 और 2011 में वनडे विश्व कप का खिताब जीता था।

तरण आदर्श ने दी ये जानकारी : युवराज सिंह वो खिलाड़ी हैं जिनके खेल के लोग दीवाने हैं। क्रिकेटर ने साल 2011 में एक ही ओवर में 6 छक्के बनाकर 36 रन बनाए और भारत को शानदार जीत दिलवाई। अब उनकी बायोपिक बनने जा रही है, जिसका लोगों को बेसब्री से इंतजार है। फिल्म समीक्षक तरण आदर्श ने एक पोस्ट जारी कर इस बात की जानकारी दी है कि अब जल्द ही युवी पर बायोपिक बनने जा रही है।

सोशल मीडिया पर उड़ी श्रेयस तलपड़े की मौत की अफवाह

हाल ही में सोशल मीडिया पर यह अफवाह उड़ी कि बॉलीवुड एक्टर श्रेयस तलपड़े का निधन हो गया है। अब इन अफवाहों पर खुद एक्टर ने रिएक्ट किया है।

श्रेयस ने इंस्टाग्राम पर एक लंबा-चौड़ा पोस्ट शेयर कर बताया कि वो जिंदा हैं और अपनी मौत की खबर पढ़कर परेशान हैं। श्रेयस ने ऐसे लोगों को भी लताड़ा जो इस तरह का भद्दा मजाक कर रहे हैं।

अपने इंस्टाग्रम अकाउंट पर चार तस्वीरें शेयर करते हुए श्रेयस ने लिखा, 'मैं सभी क्लीयर करना चाहता हूं कि मैं जिंदा हूं, खुश और हेल्दी हूं। मुझे एक पोस्ट के बारे में पता चला जिसमें दावा किया गया था कि मैं मर चुका हूं।

मैं समझता हूं कि मजाक अपनी जगह है, लेकिन जब इसका गलत इस्तेमाल होता है तब ये सचमुच किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है।

भले ही किसी ने इसे मजाक के तौर पर शुरू किया होगा, पर अब इससे बेवजह ही मेरी चिंता करने वालों और खासतौर पर मेरे परिवारवालों को परेशानी हो रही है।'

इस खबर ने मेरी बेटी का डर बढ़ा दियाः श्रेयस

एक्टर ने आगे लिखा, 'मेरी छोटी बेटी जो हर दिन स्कूल जाती है, वो पहले से मेरी हेल्थ को लेकर परेशान रहती है। वो मुझसे लगातार सवाल करती है और मेरी हेल्थ को लेकर श्योर रहना चाहती है।

इस गलत खबर ने उसके डर को और बढ़ा दिया है। वे अपने स्कूल टीचर्स और दोस्तों से और सवाल करने लगी है।'

राशिफल

मेष

सितंबर माह की शुरुआत सुखद होगी और इस दौरान आपको घर और बाहर से स्वजनों का सहयोग मिलेगा। कारोबार में लाभ की प्राप्ति होगी। कार्यक्षेत्र में सकारात्मक संभावनाएं बनेंगी, लेकिन इस दौरान आपके भीतर अहंकार की भावना बलवती हो सकती है। ऐसे में अपनी वाणी और व्यवहार से किसी दूसरे को कष्ट पहुंचाने से बचे।

मिथुन

मिथुन राशि के लिए यह माह शुभता और लाभ लिए है। लंबे समय से अटके किसी काम के पूरे होने पर आप हर्ष का अनुभव करेंगे। इस दौरान आपको सौभाग्य का पूरा साथ मिलेगा। कार्यक्षेत्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। असम्भव सा लगने वाला कार्य भी आप अपने सीनियर और जूनियर की मदद से करने में कामयाब हो जाएंगे।

सिंह

सिंह राशि के जातकों को सितंबर के महीने में अपने समय,धन एवं ऊर्जा का प्रबंधन करके चलना होगा,अन्यथा आपको बेवजह की परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। माह की शुरुआत में घर,वाहन आदि की मरम्मत या अन्य जरूरतों पर जेब से ज्यादा धन खर्च हो सकता है,जिसके चलते आपका बजट गड़बड़ा सकता है। इस माह में आपको कामकाज के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है।

तुला

तुला राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना सुख और सौभाग्य को साथ लिए हुए है। इस माह आपको हर कदम पर इष्ट-मित्रों का सहयोग मिलेगा और सोचे हुए काम समय पर पूरे होंगे। जिसके चलते आपके भीतर गजब का उत्साह और आत्मविश्वास देखने को मिलेगा। माह की शुरुआत में कोई बड़ी उपलब्धि आपकी झोली में आकर गिरेगी,जिससे आपका मान-सम्मान बढ़ेगा।

धनु

इस महीने धनु राशी के लिए की शुरुआत शुभता और सफलता लिए है। माह की शुरुआत में ही आपको करिअर और कारोबार को आगे बढ़ाने का कोई बड़ा प्रस्ताव मिल सकता है। इस दौरान आप अपनी काबिलियत के दम पर समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी खास जगह बनाने में कामयाब होंगे। कार्यक्षेत्र में तारीफ होंगी। किसी प्रभावी व्यक्ति से मुलाकात होगी जिसकी मदद से भविष्य में किसी बड़ी योजना से जुड़ने का मौका मिलेगा।

कुंभ

कुंभ राशि के लिए सितंबर का माह मिलाजुला साबित होगा। माह की शुरुआत में कार्यक्षेत्र में सीनियर और जूनियर से तालमेल बनाकर चलना उचित रहेगा। इस दौरान आपको अपने सेहत और संबंध पर विशेष ध्यान देना होगा। आपकी रुखे व्यवहार से आपके अपने नाराज होकर दूर जा सकते हैं। कार्यक्षेत्र में बड़ा पद या जिम्मेदारी मिल सकती है। जिससे आपके मान-सम्मान में बढ़ोत्तरी होगी।

वृषभ

वृष राशि के जातकों के लिए सितंबर महीने की शुरुआत में अपनी सेहत और संबंध दोनों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत रहेगी। इस दौरान आप मौसमी या फिर किसी पुरानी बीमारी के उभरने से परेशान हो सकते हैं। इस दौरान घर के किसी सदस्य के साथ हुआ विवाद आपके तनाव का बड़ा कारण बन सकता है। कारोबार में कंपटीटर से कड़ा मुकाबला करना पड़ेगा।

कर्क

कर्क राशि के जातकों के लिए सितंबर महीने की शुरुआत थोड़ी चुनौती भरी रह सकती है। माह की शुरुआत में आप पर न सिर्फ घर बल्कि कार्यक्षेत्र से जुड़ी जिम्मेदारियों का बोझ भी बना रहेगा। जिसे पूरा करने में मित्रों या फिर स्वजनों की मदद बामुश्किल ही मिल पाएगी। ऐसे में आपको दूसरों के भरोसे रहने की बजाय खुद ही चीजों को हैंडल करना होगा।

कन्या

कन्या राशि के जातकों को सितंबर महीने में अपनी महत्वाकांक्षाओं पर नियंत्रण बनाए रखना होगा। माह की शुरुआत में कार्यक्षेत्र में कामकाज का बोझ बना रहेगा और उसे समय पर खत्म करने के लिए आपको अतिरिक्त समय देना होगा। इस दौरान आपको अपने करिअर और कारोबार को लेकर सोच-समझकर ही कोई बड़ा फैसला लेना चाहिए,अन्यथा आपको लेने के देने पड़ सकते हैं।

वृश्चिक

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना बेहद शुभ और लाभप्रद साबित होगा। माह की शुरुआत लंबे समय से अटके काम के पूरे होने के साथ होगी। सत्ता-सरकार से जुड़े मामलों में मनचाही सफलता मिलेगी और धन का लाभ होगा। इस दौरान व्यवसाय में मनचाहा लाभ प्राप्त होगा। यदि आप अपने कारोबार के विस्तार की सोच रहे थे तो आपकी यह ख्वाहिश इस माह जरूर पूरी हो जाएगी।

मकर

मकर राशि के लोगों के लिए सितंबर का महीना कभी खुशी तो कभी गम लिए रहने वाला है। माह की शुरुआत में घरेलू समस्याओं के चलते मन थोड़ा परेशान रहेगा। इस दौरान कार्यक्षेत्र में कुछ परिवर्तन हो सकते हैं, जिसके चलते आपको अतिरिक्त परिश्रम और प्रयास करने की जरूरत रहेगी। हालांकि आप अपने इष्ट-मित्र की मदद से सभी चुनौतियों को पार करते हुए अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निर्वहन करेंगे।

मीन

मीन राशि के लोगों के लिए यह महीना उतार-चढ़ाव लिए रहने वाला है। माह की शुरुआत में आपको अपने करिअर और कारोबार में तमाम तरह की परेशानियों को झेलना पड़ सकता है,लेकिन इस कठिनाई भरे समय में आपके अपने हर पल साथ खड़े रहेंगे। कार्यक्षेत्र में सीनियर और जूनियर दोनों हीं आपको काम को समय पर पूरा करने में सहयोग करेंगे।

पावरग्रिड
POWERGRID
1 राष्ट्र ग्रिड फ्रिक्वेंसी
पावरग्रिड
दुनिया की सबसे बड़ी विद्युत पारेषण उपयोगिताओं में से एक
पावरग्रिड का व्यवसाय
पारेषण
• पारेषण लाइनें– 1,77,790 सर्किट किमी
• सब–स्टेशन– 278
• ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता– 5,32,446 एमवीए
परामर्श सेवाएं
• 250 से अधिक घरेलू क्लाइंट्स को पारेषण संबंधी परामर्श
• 23 देशों में वैश्विक उपस्थिति के साथ 30 से अधिक क्लाइंट्स
• पावरग्रिड लीडरशिप एकेडमी– दुनिया भर के प्रतिभागियों के लिए 550+ पाठ्यक्रम
टेलिकॉम
• 1,00,000 कि.मी. टेलिकॉम नेटवर्क का स्वामित्व एवं प्रचालन
• एनकेएन एवं एनओएफएन क्रियान्वयन में प्रमुख परामर्शदाता
भविष्योन्मुखी
• नवीनतम तकनीक द्वारा संचालित
• अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर
पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पावरग्रिड), विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार का एक महारत्न सार्वजनिक उपक्रम है, जो देश भर में पारेषण योजनाओं के नियोजन, डिजाइनिंग, वित्तपोषण, निर्माण, प्रचालन तथा विद्युत अनुरक्षण में संलग्न है और टेलिकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में भी प्रभावी उपस्थिति है।
पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
केन्द्रीय कार्यालय : "सौदामिनी", प्लॉट सं.–2, सेक्टर–29, गुरूग्राम, हरियाणा–122001, फोन : 0124-2571700-719
पंजीकृत कार्यालय: बी-9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली-110016
सीआईएन : L40101DL1989GOI038121 | वेबसाइट : www.powergrid.in | फॉलो करें
एक महारत्न पीएसयू

Postal Registration No. : RN/262/2023 25

समस्त प्रदेश एवं देशवासियों को

स्वतंत्रता दिवस

की हार्दिक शुभकामनाएं

मैं स्वतंत्र हूँ, पढ़ाई के छोटे-मोटे खर्चों से, मुझे मिला **सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का लाभ**

मैं स्वतंत्र हूँ, रोजमर्रा की आर्थिक परेशानी से, मेरा **झारखण्ड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना में हुआ निबंधन**

मैं स्वतंत्र हूँ, विदेश में उच्च शिक्षा के लिए, मुझे मिला **मरङ गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना का लाभ**

मैं स्वतंत्र हूँ, **पलाश ब्रांड** ने मुझे दिया आर्थिक स्वावलंबन

मैं स्वतंत्र हूँ, उच्च/तकनीकी शिक्षा के लिए, मुझे मिला **गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ**

मैं स्वतंत्र हूँ, कृषि ऋण की चिंता से, मुझे मिला **झारखण्ड कृषि ऋण माफ़ी योजना का लाभ**

मैं स्वतंत्र हूँ, बुढ़ापे की आर्थिक समस्या से, मुझे मिला **सर्वजन पेंशन योजना का लाभ**

मैं स्वतंत्र हूँ, बीमारी में खर्च की चिंता से, सरकार दे रही है **अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का लाभ**

आइये हमसब मिलकर झारखण्ड के वीर सपूतों और वीरांगनाओं के सोना झारखण्ड के सपनों को साकार करने में अपना योगदान दें।

हेमन्त सोरेन
मुख्यमंत्री, झारखण्ड

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखण्ड सरकार